

# 6

## मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य

### मौलिक अधिकार (Fundamental Rights)

- सर्वप्रथम लिखित रूप में व्यक्ति के अधिकारों का उल्लेख कहाँ पाया जाता है? - 1215 के मैग्नाकार्टा में
- व्यक्ति के अधिकारों का जन्मदाता किसे कहा जाता है? - मैग्नाकार्टा (1215)
- भारतीय संविधान के भाग-3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। इस भाग-3 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? - भारत का मैग्नाकार्टा
- मौलिक अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गयी थी अथवा मौलिक अधिकारों को सर्वेधानिक संरक्षण सर्वप्रथम किस देश में दिया गया था? - संयुक्त राज्य अमेरिका में
- संयुक्त राज्य अमेरिका के मूल संविधान में नागरिकों के कोई मौलिक अधिकार नहीं थे, परंतु संविधान में मौलिक अधिकारों का कब समावेश किया गया?
- किस देश के नागरिकों के मौलिक अधिकार आत्मातिक, निरपेक्ष एवं निरकुश हैं, ज्यांकि वहाँ संविधान में मौलिक अधिकारों पर निर्वधन के लिए कोई उपवंध नहीं दिये गये हैं? - संयुक्त राज्य अमेरिका
- भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित या लिया गया है? - अमेरिका के संविधान में
- ब्रिटिश नागरिकों के अधिकारों तथा स्वतंत्रता की घोषणा का उल्लेख कहाँ किया गया है? - बिल ऑफ राइट्स, 1689 में
- भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की परिभाषा कहाँ दी गयी है? - कहीं नहीं
- मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? - व्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना
- भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? - भाग-3 में
- किस अनुच्छेद में यह स्पष्ट उद्भृत है कि संसद द्वारा ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता, जिससे संविधान के भाग-3 में अवस्थित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो? - अनुच्छेद 13 में
- भारतीय संसद किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को भाग-3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है? - अनुच्छेद 368 के तहत
- किस संविधान संशोधन द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि संसद मौलिक अधिकारों में भी संविधान के अन्य उपवंधों की तरह संशोधन कर सकती है? - 17वें संविधान संशोधन (1969) द्वारा
- किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि भारतीय संसद अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है? - शंकरी प्रसाद वनाम भारत मध्य 1951 में
- 27 फरवरी, 1967 को सर्वोच्च न्यायालय ने किस विवाद में यह अभिनिर्धारित किया कि भाग-3 के प्रावधानों में संशोधन करने और मौलिक अधिकारों को समाप्त या समित करने का अधिकार संसद को नहीं है? - गोलकनाथ वनाम पंजाब राज्य में

### भाग-3

#### मूल अधिकार (अनुच्छेद 12-35)

##### साधारण

- अनुच्छेद 12: परिभाषा
- अनुच्छेद 13: मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियाँ

#### समता का अधिकार (Right to Equality)

- अनुच्छेद 14: विधि के समक्ष समता
- अनुच्छेद 15: धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध
- अनुच्छेद 16: लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता
- अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता का अंत
- अनुच्छेद 18: उपाधियों का अंत

#### स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom)

- अनुच्छेद 19: वाक-स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण
- अनुच्छेद 20: अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण
- अनुच्छेद 21: प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण
- अनुच्छेद 21-क: शिक्षा का अधिकार
- अनुच्छेद 22: कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी और निरोध संसंरक्षण

#### शोषण के विरुद्ध अधिकार

#### (Right against Exploitation)

- अनुच्छेद 23: मानव के दुर्व्यापार और बलात्‌त्रम का प्रतिषेध
- अनुच्छेद 24: कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध

#### धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार

#### (Right to Freedom of Religion)

- अनुच्छेद 25: अंतःकरण की ओर धर्म के अवाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता

## मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य

किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संसद द्वारा यह निर्धारित किया गया कि मौलिक अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है? - 24वें संशोधन अधिनियम, 1971  
सर्वोच्च न्यायालय ने 24वें संविधान संशोधन द्वारा संसद को प्रदत्त संशोधन के अधिकार पर निर्वधन लगा दिया और यह अभिनिर्धारित किया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती?

- केशवानंद भारती बनाम केरल गन्ध (1973)

सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय को निष्प्रभावी करने के उद्देश्य से संसद ने किस संशोधन अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया कि संसद की संविधान संशोधन की शक्ति असीमित है और संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनाता नहीं दी जा सकती?

- 42वें संशोधन अधिनियम, 1976 के तहत

किस मामले में न्यायालय ने 42वें संविधान संशोधन को असंवैधानिक घोषित हुए पुनः यह अभिनिर्धारित किया कि संसद संविधान के मौलिक ढांचे को बदल नहीं सकती?

- मिनर्व मिल्स मामले में

सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों को किस मामले में आधारित लक्षण नहीं माना - केशवानंद भारती मामले में था?

भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों के प्रयोजन के लिए 'राज्य' शब्द को परिभाषित किया है? - अनुच्छेद 12 में

किस अनुच्छेद में व्यवस्था है कि कोई भी कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर पारित किया गया है, तो उसे अमान्य माना जायेगा? - अनुच्छेद 13

भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राकृतिक न्याय की अवधारणा निहित है? - अनुच्छेद 14

भारतीय नागरिकों को भाग-3 में प्राप्त मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकों के अन्य अधिकार दिये गये हैं? - अनुच्छेद 265, 300क, 301

किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि विदेश जाने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है? - मेनका गांधी बनाम भारत मंड़, 1978

किस मामले में फैसला सुनाते हुए न्यायालय ने मौलिक अधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों से श्रेष्ठ घोषित किया था? - गोलकनाथ मामले में

किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए एक नयी संविधान सभा बुलानी पड़ेगी? - गोलकनाथ के मामले में

गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले को अप्रभावी बनाने के लिए संसद ने कौन-सा संविधान संशोधन पारित किया था? - 24वा संविधान संशोधन

अब तक सर्वोच्च न्यायालय के किस संवैधानिक पीठ में सबसे अधिक (13) न्यायाधीश थे? - केशवानंद भारती बनाम केरल गन्ध में

किस मामले में न्यायालय ने कहा कि निर्देशक तत्व शासन के आधारभूत सिद्धांत हैं और मौलिक अधिकारों को इनके माध्यम से ही समझा जा सकता है? - मन्जन मिंह बनाम राजस्थान मामले में

आपात स्थिति में भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकारों का निलम्बन कर सकता है? - अनुच्छेद 358

सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले की व्याख्या करते हुए यह अभिनिर्धारित किया था कि अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते समय न केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सहारा लिया जायेगा बल्कि उचित प्रक्रिया या सम्यक प्रक्रिया या युक्ति-युक्ति प्रक्रिया का सहारा लिया जायेगा?

- मेनका गांधी बनाम भारत संघ

- अनुच्छेद 26: धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता

- अनुच्छेद 27: किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदर्भ के बारे में स्वतंत्रता

- अनुच्छेद 28: कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपस्थिति होने के बारे में स्वतंत्रता

### संस्कृति और शिक्षा संवर्धी अधिकार

(Cultural and Educational Rights)

- अनुच्छेद 29: अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण

- अनुच्छेद 30: शिक्षा संस्थाओं को स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार

- अनुच्छेद 31: सम्पत्तियों का अनिवार्य अधिग्रहण (निरसित)

### कुछ विधियों की व्यावृत्ति

(Saving of Certain Laws)

- अनुच्छेद 31क: सम्पत्तियों आदि के अंतर्गत के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति

- अनुच्छेद 31ख: कुछ अधिनियमों और विधिमान्दकरण

- अनुच्छेद 31ग: कुछ निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति

- अनुच्छेद 31घ: एट्रिविंग्डी गतिविधियों के संबंध में कानूनों का वचाव (निरसित)

### संविधानिक उपचारों का अधिकार

(Right to Constitutional Remedies)

- अनुच्छेद 32: इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए उपचार

- अनुच्छेद 32क: अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कार्यवाहीयों में राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं (निरसित)

- अनुच्छेद 33: इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का वलों आदि जो लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति

- अनुच्छेद 34: जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है, तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्वधन

- अनुच्छेद 35: इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान

## विषय NCERT भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान सार संग्रह (By : Khan Sir, Patna)

- मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्वों में से किसको न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं कराया जा सकता? - **राज्य के नीति निदेशक तत्व**
- किस संविधान संशोधन अधिनियम में यह कहा गया कि राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए पास किये गये किसी कानून को इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि वह अनुच्छेद 14, 19 तथा 31 में दिये गये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है? - **42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1976**  
**(नोट:** इसी संशोधन अधिनियम के तहत राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी गयी। )
- मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या सात थी। वर्तमान में इनकी संख्या कितनी हो गयी है? - **मात्र छह**  
(1. समता का अधिकार, 2. स्वतंत्रता का अधिकार, 3. शोषण के विरुद्ध अधिकार, 4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, 5. संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और 6. सांविधानिक उपचारों का अधिकार)
- सम्पत्ति का अधिकार, जिसे अनुच्छेद 31 में दिया गया था, किस संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया? - **44वें संविधान संशोधन (1978) द्वारा**
- भारतीय नागरिकों को कौन-से और कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जबकि विदेशियों को नहीं? - **चार (अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29)**
- कौन-से मौलिक अधिकार कार्यपालिका एवं विधायिका दोनों पर प्रतिबंध लगाते हैं? - **अनुच्छेद 15, 17, 18, 20 एवं 24**
- कौन-सा मौलिक अधिकार सिर्फ कार्यपालिका पर प्रतिबंध लगाता है, विधानमंडल पर नहीं? - **अनुच्छेद 21**
- किस अनुच्छेद के तहत समानता एवं कानून के समान संरक्षण की व्यवस्था की गयी है, जिसका अपवाद राष्ट्रपति एवं राज्यपाल द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान किये गये आपराधिक मामलों के संदर्भ में हैं? - **अनुच्छेद 14 के तहत**
- अनुच्छेद 14 के अंतर्गत 'विधि के समक्ष समता' तथा 'विधियों के समान संरक्षण' शब्दावली किस देश के संविधान से प्रेरित है? - **क्रमशः ब्रिटिश एवं मंयुक्त राज्य अमेरिका**
- किस अनुच्छेद के तहत राज्य नागरिकों के बीच केवल धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद नहीं करेगा? - **अनुच्छेद 15(1)**
- राज्य 'सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों' के लिए शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत प्रदान करता है? - **अनुच्छेद 15(4)**
- किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15(4) को संविधान में जोड़ा गया? - **प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा**
- कौन-सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? - **धर्म, जाति, वर्ण, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा**
- किस अनुच्छेद में सभी नागरिकों को लोक नियोजन में अवसर की समानता प्रदान की गयी है? - **अनुच्छेद 16(1) में**
- किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि राज्य के नियोजन में धर्म, जाति, मूलवंश, जन्मस्थान, लिंग, उद्भव, निवास स्थान के आधार पर विभेद नागरिकों के बीच नहीं किया जायेगा? - **अनुच्छेद 16(2)**
- अनुच्छेद 16(3) द्वारा किसको यह शक्ति प्रदान की गयी है कि वह विधि बनाकर सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए उस राज्य में निवास की योग्यता को शामिल करें? - **संसद को**

### समानता क्या है?

समानता का तात्पर्य यह है कि समाज में किसी व्यक्ति या वर्ग से जाति, रंग, क्षेत्र, धर्म और आर्थिक स्तर पर भेदभाव का निषेध तथा सबको समान अवसर प्राप्त हो। लास्की का कहना है, “सर्वप्रथम समानता का अर्थ है कि समाज में कोई विशेषाधिकार युक्त वर्ग न हो।” समानता पांच प्रकार की होती है— प्राकृतिक समानता, सामाजिक समानता, नागरिक वैधानिक समानता, राजनीतिक समानता और आर्थिक समानता। प्राकृतिक समानता के तहत प्रत्येक मनुष्य को प्राकृतिक रूप से समानता प्राप्त होती है, जबकि सामाजिक समानता के अंतर्गत समाज में सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाता है और सभी को सामाजिक अवसरों का लाभ प्राप्त होता है। नागरिक वैधानिक समानता का अर्थ है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हों तथा कानून किसी भी व्यक्ति से जाति, धर्म, नस्ल, वंश और लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं हो। जब सभी नागरिकों को राज्य द्वारा समान राजनीतिक अधिकार, मताधिकार आदि प्राप्त हों तो इसे राजनीतिक समानता कहते हैं। आर्थिक समानता का अर्थ है कि किसी व्यक्ति को अपने मौलिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी को समान रोजगार, समान वेतन, व्यवसाय और समान रूप से आर्थिक कार्य करने का अधिकार हो तो ऐसी समानता को आर्थिक समानता कहते हैं। समाज में नागरिकों के लिए समानता विकास के लिए आवश्यक शर्त है, क्योंकि समानता के बिना कोई भी व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का वास्तविक उपभोग नहीं कर सकता है।

### किसे कहते हैं विधि का शासन?

विधि के शासन (Rule of Law) का प्रतिपादन ब्रिटिश विचारक ए. वी. डायसी ने अपनी पुस्तक "The British Constitution" में किया था। विधि का शासन दो उपसिद्धांतों पर आधारित है-

**विधि के समक्ष समानता:** 'विधि के समक्ष समानता' शब्द ब्रिटिश संविधान से लिया

## मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य

- किस अनुच्छेद के तहत सरकार राज्य के नियोजन में सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए विशेष उपबंध कर सकेंगी? - **अनुच्छेद 16(4)**
  - किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 16 में एक नया उपबंध (4ख) जोड़ा गया है, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पूर्व की अपूरित रिक्तियों में 50% को सीमा को समाप्त करता है, जो रिक्तियां विगत वर्षों में यांग उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने के कारण नहीं भरी जा सकी थीं?
- 81वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2000 द्वारा

गया है, जिसका तात्पर्य यह है कि विधि की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान हैं, चाहे उसकी सामाजिक स्थिति कुछ भी क्यों नहीं। यह प्रावधान राज्य के ऊपर एक नकारात्मक प्रतिबंध आरोपित करता है, अर्थात् राज्य किसी ऐसे कानून का निर्माण नहीं करेगा, जो असमानता को बढ़ावा दे। अनुच्छेद 14

### मौलिक अधिकार संबंधी महत्वपूर्ण वाद एवं संशोधन

- **रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य** के मामले में 1950 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रकाशन की स्वतंत्रता भी समिलित है।
- **शंकरी प्रमाद बनाम भारत संघ (1951)** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि भारतीय संसद अनुच्छेद 368 के तहत मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है।
- **चंपकम दोगायजन वाद (1952)** में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य के निदेशक तत्व 'वादयोग्य' नहीं हैं, जबकि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय लेख और आदेश जारी कर सकते हैं।
- **मञ्जन मिंह बनाम राजस्थान मामले (1964)** में न्यायालय ने कहा कि राज्य के निदेशक तत्व शासन के आधारभूत सिद्धांत हैं और मौलिक अधिकारों को इनके माध्यम से ही समझा जा सकता है।
- **मर्वोच्च न्यायालय** ने **गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967)** के निर्णय में अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मौलिक अधिकारों में संशोधन पर रोक लगा दी, अर्थात् संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। इसी मामले में फैसला सुनाते हुए न्यायालय ने मौलिक अधिकारों को नीति निदेशक तत्वों से श्रेष्ठ बताया।
- **चंद्रभवन बोर्डिंग और लॉजिंग बनाम मैमूर राज्य (1967)** के मामले में न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं।
- **24वें संविधान संशोधन (1971)** गोलकनाथ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से उत्पन्न स्थिति के संदर्भ में पारित किया। इसके तहत अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन किया गया तथा यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में दो गयी प्रक्रिया द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है।
- **कंशवानंद भारती बनाम कंरल राज्य** के निर्णय में इस प्रकार के संशोधन को विधिमान्यता प्रदान की गयी अर्थात् गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को निरस्त कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने 24वें संविधान संशोधन द्वारा संसद को प्रदत्त संशोधन के अधिकार पर निर्वधन लगा दिया और यह अभिनिर्धारित किया कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढाँचे को परिवर्तित नहीं कर सकती।
- **42वें संविधान संशोधन (1976)** द्वारा अनुच्छेद 368 में छंड 4 और 5 जोड़े गये तथा यह व्यवस्था की गयी कि संसद की संविधान संशोधन की शक्ति असीमित है और संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनावी नहीं दी जा सकती।
- **मेनका गांधी बनाम भारत संघ, 1978** के मामले की व्याख्या करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि विदेश जाने का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है।
- **मिनर्व मिल्स बनाम भारत संघ (1980)** के निर्णय द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनर्विलोकन कर सकता है। साथ ही, न्यायालय ने 42वें संशोधन को असंवैधानिक बताते हुए पुनः यह अभिनिर्धारित किया कि संसद संविधान के मौलिक ढाँचे को बदल नहीं सकती। इसी मामले में न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि मौलिक अधिकार एवं निदेशक तत्व दोनों ही संविधान के अभिन अंग हैं एवं एक-दूसरे के पूरक हैं।
- **रणधीर मिंह बनाम भारत संघ, 1982** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि समान कार्य के लिए समान वंतन (अनुच्छेद 14 के तहत) एक मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि निदेशक तत्व (अनुच्छेद 39घ) है, लेकिन यह एक संवैधानिक प्रावधान है, इसलिए यदि राज्य समान कार्य के लिए विभेदपूर्ण वंतन देता है तो न्यायालय उनमें हस्तक्षेप करेगा।
- **मोड़न मिंह बनाम न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी (1989)** के मामले की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि फुटपाथों पर व्यापार करना अनुच्छेद 19(1)(छ) के अधीन एक मौलिक अधिकार है और उस पर केवल अनुच्छेद 19(6) के अधीन निर्वधन लगाये जा सकते हैं।

## किंवदं NCERT भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान सार संग्रह (By : Khan Sir, Patna)

- 85वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2001 द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया है ताकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सरकारी कर्मचारियों को आरक्षण नियमों के तहत पदोन्नति के मामले में आनुपर्याप्त प्रदान की जा सके? - **अनुच्छेद 16(4ए)**
- किस अनुच्छेद द्वारा उन विधियों के लागू होने को अनुच्छेद 16(1)(2) के प्रभाव से बचाता है कि जो किसी धार्मिक संस्था के पद पर नियुक्ति के लिए किसी विशेष धर्म की जानकारी रखने की योग्यता निहित करता है? - **अनुच्छेद 16(5)**
- भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त 'समाजवाद' शब्द को किन अनुच्छेदों को साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई? - **अनुच्छेद 14 और 16**
- भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? - **अनुच्छेद 17 में**
- भारत में किसी भी रूप में स्पृश्यता के आचरण को निषिद्ध करने का प्रावधान किस अधिनियम द्वारा लागू होता है? - **अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955**
- अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, 1955 को 1976 में संशोधित कर इसका नाम 'नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955' कर दिया गया। 1989 में इस अधिनियम को और कठोर बनाते हुए क्या नाम दिया गया? - **अनुसूचित जाति व जनजाति निरोधक कानून, 1989**
- अनुच्छेद 18(1) राज्य को, किसी व्यक्ति को, चाहे वह भारतीय नागरिक हो या विदेशी नागरिक हो, उपाधियां प्रदान करने का प्रतिबंध करता है। किससे संबंधित विशिष्ट सम्मान के मामले में इसको अपवाद माना जाता है? - **मेना तथा विद्या**
- भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के मुताबिक भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि तथा अनुच्छेद 18(4) के मुताबिक राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई गैर उपलब्ध या पद किसकी सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा? - **राष्ट्रपति**
- क्या भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री इत्यादि उपाधियों को प्रदान किया जाना अनुच्छेद 18 का उल्लंघन है? - **नहीं**  
(क्योंकि प्राप्तकर्ता द्वारा इनको उपाधि के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता या नाम के साथ उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में व्यवहार में नहीं लाया जा सकता।)
- संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 किस प्रकार की व्यवस्था है? - **सामाजिक समता कौन-सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए छह स्वतंत्रताएं सुनिश्चित करता है, जिनमें भाषण एवं अधिव्यक्ति, सभा, संगम या संघ बनाने, भ्रमण, आवास एवं वृत्ति व्यवसाय करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है?** - **अनुच्छेद 19**
- क्या अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त स्वतंत्रताओं पर प्रतिबंध लगाये जा सकते हैं? - **हाँ**  
न्यायपालिका द्वारा विभिन्न मामलों के तहत किस अनुच्छेद का विश्लेषण कर यह निर्णय दिया कि 'प्रेस की स्वतंत्रता, सूचना प्राप्त करने का अधिकार और झण्डा फहराने का अधिकार' विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ही शामिल है? - **अनुच्छेद 19(1ए)**
- 'प्रेस की स्वतंत्रता' किस अधिकार में निहित है? - **भाषण स्वतंत्रता**  
किसी राजनीतिक दल का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जा सकता है?
- अनुच्छेद 19 के तहत विधायिका द्वारा निर्धारित किये गये तर्कसंगत निर्वध की जांच किसके द्वारा की जाती है? - **न्यायिक पुनर्विलोकन**

में कहा गया है कि कानून के समक्ष सभी समान हैं।

**विधि का समान संरक्षण:** 'विधि का समान संरक्षण' शब्द अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जिसका तात्पर्य यह है कि समान स्थिति वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान कानून, अर्थात् समानों के साथ समानता और असमानों के साथ असमानता। यह एक सकारात्मक अवधारणा है।

### समानता के अधिकार के अपवाद

- विदेशी राजनायिकों को
- अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति वराज्यपाल
- अनुच्छेद 105 के तहत संसद सदस्य
- अनुच्छेद 361(क) के तहत प्रेस
- अनुच्छेद 194 के तहत विधानमंडल के सदस्य

**नोट:** उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 का उदार विवेचन करते हुए अनेक अधिकारों को शामिल किया है, जो निम्नवत हैं-

1. आजीविका का अधिकार
2. अच्छे स्वास्थ्य का अधिकार
3. भोजन का अधिकार
4. शिक्षा पाने का अधिकार 21(क)
5. निजता का अधिकार
6. स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार आदि।

### स्वतंत्रता क्या है?

किसी भी लोकतंत्र में समता और स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। इनमें से एक के बिना दूसरे की कल्पना नहीं की जा सकती। स्वतंत्रता का अर्थ है चिंतन, अभिव्यक्ति और कार्य करने की स्वतंत्रता। लेकिन स्वतंत्रता का यह अर्थ नहीं है कि हम जैसा चाहें वैसा करने लगें। स्वतंत्रता को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि बिना किसी अन्य की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाए और बिना कानून व्यवस्था को ठेस पहुंचाए, प्रत्येक व्यक्ति अपनी-अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले सके। सामान्य अर्थों में, व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। हालांकि प्रतिबंधों का न होना स्वतंत्रता का केवल एक पहलू है। स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति की

- 1950 : तथा अ
- जब अ
- निलम्बि
- यदि 3
- अनुच्छे
- की घे
- सर्वोच्च
- माना
- किस
- फुटप
- और
- राज्य
- विक्र
- मौलि
- किस
- यह
- व अ
- का :
- किस
- नहीं
- का
- अप
- भार
- विद्यि
- प्रभा
- किर
- अधि
- अनु
- का
- किस
- साध
- कि
- प्रवि
- आ
- सब
- 'वि
- कि

## मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य

■ 1950 में किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में प्रकाशन की स्वतंत्रता भी सम्मिलित है?

- रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य में

■ जब अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल उद्घोषणा की जाती है, तब कौन-सा अनुच्छेद निलम्बित हो जाता है?

- अनुच्छेद 19

■ यदि आपात स्थिति की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण की गयी हो, तो अनुच्छेद 19 में प्रदत्त स्वतंत्रताएं स्वतः निलम्बित हो जाती हैं; किंतु अगर आपात स्थिति की घोषणा अनुच्छेद 359 के संदर्भ में की जाये, तो किसको आदेश जारी करना होगा कि कौन-कौन से अधिकारों को निलम्बित किया जा रहा है? - गण्डपति को

■ सर्वोच्च न्यायालय ने किन अनुच्छेदों के तहत चलचित्रों पर प्री-सेंसरशिप को संवैधानिक माना है?

- अनुच्छेद 19(1)(क) और (ख)

■ किस मामले की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि फुटपाथों पर व्यापार करना अनुच्छेद 19(1)(छ) के अधीन एक मौलिक अधिकार है और उस पर केवल अनुच्छेद 19(6) के अधीन निर्बंधन लगाये जा सकते हैं?

- सोडन सिंह बनाम न्यू दिल्ली मूनिसिपल कमेटी के मामले

■ राज्य संचालित लाटरी व्यापार या बाणिज्य नहीं, जुआ है। इसलिए राज्य द्वारा उसके विक्रय पर लगायी रोक लगाना संवैधानिक है। लाटरी पर रोक किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती है? - अनुच्छेद 19(1)(छ)

■ किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने केरल उच्च न्यायालय के निर्णय को पुष्ट करते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि राजनीतिक दलों द्वारा बंद का आयोजन करना असंवैधानिक व अवैध है तथा बंद राष्ट्रीय नुकसान के अलावा संविधान के अनुच्छेद 19(1) और 21 का उल्लंघन करते हैं? - माकपा बनाम भरत कुमार व अन्य के मामले में

■ किस अनुच्छेद के अनुसार, "किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए तब तक सिद्धांदोष नहीं ठहराया जायेगा, जब तक कि उसने ऐसा कार्य करने के समय किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण न किया हो। वह उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के किये जाने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन लगाई जा सकती थी"?

- अनुच्छेद 20(1) के अनुसार

■ भारतीय संसद एवं राज्य विधानमंडलों को भूतलक्षी और भविष्यलक्षी दोनों प्रकार के विधियों के निर्माण की स्वतंत्रता है, परंतु विधानमंडल ऐसी कोई विधि को भूतलक्षी प्रभाव नहीं दे सकता है, जो दण्ड (फौजदारी) के उद्देश्य से की गयी हो?

- अनुच्छेद 20(1) के तहत

■ किस अनुच्छेद के मुताबिक, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता? - अनुच्छेद 20(2)

■ अनुच्छेद 20(2) के तहत दोहरे दण्ड से संरक्षण (Protection from Double Jeopardy) का सिद्धांत किससे लिया गया है?

- अमेरिकन विधि से

■ किस अनुच्छेद के अनुसार, किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा? - अनुच्छेद 20(3)

■ किस अनुच्छेद के द्वारा व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही वंचित किया जा सकता है अथवा नहीं? - अनुच्छेद 21

■ आपात स्थिति की उद्घोषणा के बावजूद किन अनुच्छेदों को निलम्बित नहीं किया जा सकता?

- अनुच्छेद 20 व 21

■ 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' किस देश के संविधान से प्रेरित है? - जापान के संविधान से

■ किस मामले में अनुच्छेद 21 की विस्तृत व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गयी थी?

- मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978

**आत्म-** अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना और उसके अंदर की संभावनाओं को विकसित करना भी है। इस अर्थ में स्वतंत्रता वह स्थिति है, जिसमें लोग अपनी रचनात्मकता और क्षमताओं का विकास कर सकें। नकारात्मक स्वतंत्रता उस क्षेत्र को पहचानने और बचाने का प्रयास करती है, जिसमें व्यक्ति अनुलंभनीय हो, जिसमें वह जो होना, बनना या करना चाहे हो सके, वन सके और कर सके। सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधरों का मानना है कि व्यक्ति केवल समाज में ही स्वतंत्र हो सकता है, समाज से बाहर नहीं और इसीलिए वह इस समाज को ऐसा बनाने का प्रयास करते हैं, जो व्यक्ति के विकास का रास्ता साफ करे। दूसरी ओर नकारात्मक स्वतंत्रता का सरोकार अहस्तक्षेप के अनुलंभनीय क्षेत्र से है, इस क्षेत्र से बाहर समाज की स्थितियों से नहीं।

**क्या भारत रत्न जैसी उपाधियाँ अनुच्छेद 18 का उल्लंघन हैं?**

भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री इत्यादि उपाधियों को प्रदान किया जाना अनुच्छेद 18 का उल्लंघन नहीं है। ये सम्मान क्रियाकलापों के विविध क्षेत्रों में नागरिकों द्वारा किये गये अच्छे कार्यों की राज्य द्वारा दी गयी मान्यता के प्रतीक मात्र हैं। इन्हें उपाधि के रूप में या उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में व्यवहार में नहीं लाया जा सकता। राज्य द्वारा उत्कृष्ट सामाजिक सेवा के लिए नागरिकों को कोई सम्मान या पुरस्कार देना संविधानसम्मत है। लेकिन इस सम्मान का उपाधि के रूप में अर्थात् अपने नाम के साथ जोड़कर उपयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए भारत रत्न या पद्म विभूषण का प्राप्तकर्ता द्वारा उपाधि के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता और इसलिए यह संविधान में प्रतिषेध के अधीन नहीं आते हैं। हालांकि इस आशंका में जनता पार्टी की सरकार ने 1978 में इन उपाधियों को देने की प्रथा को बंद कर दिया था, परंतु श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार ने 1980 में इन उपाधियों को देने की प्रथा को पुनः शुरू किया, जो आज तक विद्यमान है।

कित्तृपुण NCERT भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान सार संग्रह (By : Khan Sir, Patna)

- शिक्षा के अधिकार के तहत राज्य को 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करानी होगी। इसको मौलिक अधिकार बनाकर संविधान में कौन-सा अनुच्छेद जोड़ा गया है? - अनुच्छेद 21 'ए'
  - भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21(ए) को किस संविधान संशोधन द्वारा अंतःस्थापित किया गया? - 86वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 द्वारा
  - अनुच्छेद 21(ए) के फलस्वरूप पारित निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बाल अधिकार (आरटोई) अधिनियम, 2009 को देश में कब लागू किया गया? - 1 अप्रैल, 2010 को
  - कौन-सा महत्वपूर्ण मानव अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा सुरक्षित है? - जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार
  - मौलिक अधिकारों के किस अनुच्छेद को मैग्नाकार्टी की संज्ञा दी जाती है? - अनुच्छेद 21 को
  - न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) केएस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ के मामले में अगस्त 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि टेलीफोन टेप करना व्यक्ति के एकांतता के अधिकार (Right to Privacy) में सौधा हस्तक्षेप है और इसका प्रयोग राज्य को तभी करना चाहिए, जब सार्वजनिक आपात या लोक सुरक्षा के लिए आवश्यक हो। एकांतता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में सम्मिलित है? - अनुच्छेद 21
  - चौदूसीएन बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत किस अधिकार को एक मौलिक अधिकार माना और यह अभिनिर्धारित किया कि जो लोग खाद्य सामग्री खरीदने में असमर्थ हैं, उन्हें राज्य द्वारा खाद्य सामग्री मुफ्त पाने का मूल अधिकार है? - भाजन का अधिकार (Right to Food)
  - बचा से काना में पड़ी महाराष्ट्र की नई अरुणा शानबाग के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 9 मार्च, 2018 को अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार के अंतर्गत मरने का अधिकार शामिल नहीं है। लेकिन उसने अरुणा शानबाग की किस प्रकार को मृत्यु को मान्यता प्रदान की? - निष्क्रिय इच्छामृत्यु (Passive Euthanasia)
  - देश की 67 प्रतिशत आबादी को सस्ती दरों पर अनाज मुहैया कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस तिथि को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के उपरांत देशभर में लागू हो गया? - 12 सितंबर, 2013 को
  - राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाम अरुणाचल प्रदेश राज्य के मामले में (चकमा शरणार्थियों के मामले में) सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि अनुच्छेद 21 का संरक्षण नागरिकों के साध-साध किसको भी उपलब्ध होगा? - विदेशियों को भी
  - क्या आपातकाल में सरकार अनुच्छेद 20 तथा 21 के तहत मिले अधिकारों का हनन कर सकती है और व्यक्ति के अधिकारों पर रोक लगा सकती है? - नहीं
  - किस अनुच्छेद में दो प्रकार की विधियों का प्रावधान है, एक सामान्य विधि एवं एक निवारक निरोध विधि? - अनुच्छेद 22
  - अनुच्छेद 22 में उन शर्तों का वर्णन किया गया है, जिसका पालन नहीं करने पर किसी व्यक्ति को उसकी दैहिक स्वतंत्रता से वर्चित करना विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार नहीं माना जायेगा। यह किस अनुच्छेद का पूरक माना जाता है? - अनुच्छेद 21
  - अनुच्छेद 22(1) के अनुसार, किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी बिना उसे कारण बताये नहीं की जायेगी। इसके अनुसार किसी बंदी व्यक्ति को कितने घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जायेगा एवं उसे अपनी पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा? - 24 घंटे के भीतर
  - परंतु उपर्युक्त संरक्षण किन दो प्रकार के व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होता है? - ग्रनु देश के व्यक्ति को एवं निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति को
  - भारतीय संविधान में निवारक निरोध का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? - अनुच्छेद 22(4) से (7) तक

**न्यायिक पुनर्विलोकन से क्या तात्पर्य है?**

न्यायिक पुनर्विलोकन न्यायालयों की एक महत्वपूर्ण शक्ति है। प्रोफेसर कार्विन के अनुसार, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति न्यायालयों की वह शक्ति है जिसके माध्यम से वे विधायका द्वारा पारित विधियों, सर्विधियों एवं अधिनियम की संवैधानिकता का परीक्षण करते हैं। इसके माध्यम से न्यायालय द्वारा ऐसी किसी भी विधि के प्रवर्तन से इनकार किया जा सकता है जो संविधान के उपबंधों से असंगत है। न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति न्यायालयों की साधारण अधिकारिता के तहत आती है बस्तुतः यह विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की शक्तियों के प्रयोग पर नियंत्रण रखने की एक अहम शक्ति है। इसके तहत न्यायालय व्यवस्थापिका के उन कानूनों को असंवैधानिक या अमान्य घोषित कर सकते हैं जो उनके मतानुसार संविधान के प्रतिकूल हो। न्यायालय इसके अंतर्गत कार्यपालिका के उन आदेशों को भी अवैध करार देसकता है जो कानून संविधान के प्रतिकूल हो।

## मैग्नाकार्टा किसे कहते हैं?

मैग्नाकार्ट, जिसको आजादी का महान चार्टर कहा जाता है, ब्रिटेन का एक कानूनी परिपत्र है जो सन् 1215 में जारी हुआ। इसको लैटिन भाषा में लिखा गया था। इसमें इंग्लैण्ड के राजा जॉन ने सामंतों को कुछ अधिकार दिये, कुछ कानूनी प्रक्रियाओं के पालन का वचन दिया, और स्वीकार किया कि उनकी इच्छा कानून के सीमा में बंधी रहेगी। इसके तहत प्रजा के कुछ अधिकारों की रक्षा की स्पष्ट रूप से पुष्टि की गयी, जिनमें से बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका (*Habeas Corpus*) उल्लेखनीय है। इसके तहत पहली बार राजा सहित सभी नागरिकों को कानून के दायरे में लाया गया। वास्तव में, इसके अंतर्गत यह बात रखी गयी थी कि राजा अपनी प्रजा को बिना किसी गलती के, किसी भी प्रकार की सजा नहीं देसकता

## मौलिक अधिकार, नीति निवेशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य

अनुच्छेद 22(4) के अनुसार किसी व्यक्ति को निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति को 3 महीने से अधिक समय तक निरुद्ध रखने के लिए किसकी सलाह की आवश्यकता होती है?

- सलाहकार बोर्ड की

इस सलाहकार बोर्ड का गठन किन व्यक्तियों से मिलकर होता है?

- उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, या न्यायाधीश रह चुके हों।

या न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो

क्या निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति के मौलिक अधिकार बने रहते हैं? - हां

क्या निवारक निरोध अधिनियम केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा पारित किया जा सकता है? - हां

संघ सरकार किन आधारों पर निवारक निरोध अधिनियम पारित कर सकती है?

- राष्ट्रपति सुरक्षा, विदेश कार्य एवं रक्षा की दृष्टि से

राज्य सरकार किन आधारों पर निवारक निरोध अधिनियम पारित कर सकती है? - लोक व्यवस्था, राज्य की सुरक्षा एवं जनता को सेवाएं प्रदान करने के लिए

किस अनुच्छेद के अनुसार, मनुष्यों का व्यापार, बेगर एवं अन्य प्रकार से कराया जाने वाला बलपूर्वक श्रम निषिद्ध है एवं इसका उल्लंघन दंडनीय अपराध है? - अनुच्छेद 23

अनुच्छेद 23 की कोई शर्त या कोई उपबंध किस प्रकार की सेवाओं पर प्रतिबंध नहीं लगाता? - राष्ट्रीय सेवाओं एवं सामाजिक सेवाओं पर

किन व्यक्तियों के द्वारा किया गया कार्य अनुच्छेद 23 के अंतर्गत नहीं आता है? - दोषित व्यक्ति या दोष मिल्द्वा व्यक्ति के द्वारा

शोषण से मुक्ति के लिए संसद ने कौन-सा अधिनियम पारित किया, जिसका उद्देश्य केवल बंधुआ मजदूर को मुक्त करना ही नहीं, बल्कि इनके पुनर्वास की व्यवस्था करना भी था? - बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम, 1976

किस अनुच्छेद के अनुसार, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों, खानों एवं अन्य जोखिम वाले कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है? - अनुच्छेद 24

भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों के अंतर्गत प्रदान किया गया है अथवा कौन-से अनुच्छेद भारत को पंथनिरपेक्ष राज्य के रूप में स्थापित करते हैं? - अनुच्छेद 25 से 28 तक

धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या तात्पर्य है?

- राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और राज्य सभी धर्मों के प्रति सम्भाव रखेगा

किस अनुच्छेद के तहत सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है, तथा बिना रोक-टोक के धर्म में विश्वास रखने, धार्मिक कार्य करने तथा प्रचार करने का अधिकार है? - अनुच्छेद 25 के तहत

अनुच्छेद 25(2)(क) और (ख) के अंतर्गत राज्य व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध किन आधारों पर लगा सकता है?

- सामाजिक व्यवस्था, सदाचार एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से

किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने, संस्था स्थापित करने, सम्पत्ति के अर्जन एवं उसके प्रशासन का अधिकार प्रदान किया गया है? - अनुच्छेद 26

किस अनुच्छेद के अनुसार धार्मिक आधार पर किसी व्यक्ति को कर देने के लिए वाध्य नहीं किया जा सकता? - अनुच्छेद 27

कौन-सा अनुच्छेद धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान देता है? - अनुच्छेद 27

किस अनुच्छेद के अनुसार सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती? - अनुच्छेद 28 के अनुसार

था या उसे जेल में बंदी बनाकर नहीं रख सकता था। मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान का मैग्नाकार्टा कहा जाता है।

### निवारक निरोध

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 संसद को निवारक निरोध का उपबंध करने वाला ऐसा कानून बनाने का अधिकार देता है, जिसमें यह निर्धारित किया गया हो कि किसी व्यक्ति को किन परिस्थितियों में, किस वर्ग के मामलों में, अधिक से अधिक कितनी अवधि के लिए निरुद्ध किया जा सकता है अथवा उसकी आजादी के अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। संसद द्वारा 1950 ई. में निवारक निरोध अधिनियम पारित किया गया, समय-समय पर इसकी अवधि भी बढ़ायी गयी, लेकिन 31 दिसंबर, 1969 से इसकी अवधि में विस्तार नहीं किया गया।

### पांच प्रकार के प्रलेख (रिट)

**बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रलेख (Writ of Habeas Corpus):** यह प्रलेख किसी ऐसे व्यक्ति की रिहाई के लिए जारी किया जाता है, जिसे अवैधानिक ढंग से बंदी बनाया गया हो। ऐसे व्यक्ति द्वारा न्यायालय में प्रार्थना किये जाने पर न्यायालय उस व्यक्ति को हिरासत में लेने वाले अधिकारी को यह आदेश देता है कि बंदी व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करा। यदि उसके बंदी बनाये जाने का कारण विधिपूर्ण नहीं है तो वह उस व्यक्ति को तुरंत रिहा करने का आदेश जारी करता है। यह प्रलेख सरकारी अधिकारियों के अतिरिक्त निजी संगठनों तथा साधारण व्यक्तियों के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है।

**परमादेश प्रलेख (Writ of Mandamus):** यह प्रलेख किसी व्यक्ति अथवा सार्वजनिक संस्था को उसके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन कराने के लिए जारी किया जाता है, किंतु यह आदेश किसी स्विवेकीय कर्तव्य के निर्वहन के लिए नहीं दिया जा सकता।

## किंतु NCERT भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान सार संग्रह (By : Khan Sir, Patna)

- अनुच्छेद 28 के तहत किस प्रकार की शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा देने पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है?
  - राज्य से प्रशासित, किंतु किसी दूसरा स्थापित संस्थाओं में
- किस अनुच्छेद के तहत भारत राज्यक्षेत्र में निवास करने वाले प्रत्येक भारतीय नागरिक को अपनी संस्कृति, लिपि और भाषा को सुरक्षित रखने का अधिकार है? - **अनुच्छेद 29**
- अनुच्छेद 29(2) के अनुसार, राज्य पोषित शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के संबंध में किस आधार पर विभेद नहीं किया जायेगा?
  - धर्म, जाति, मूलवंश और भाषा अथवा इनमें से किसी भी आधार पर
- किस अनुच्छेद के अनुसार, सभी अल्पसंख्यकों को अपनी इच्छानुसार शिक्षण संस्थाओं की स्थापना एवं उनका प्रबंध करने का अधिकार है तथा राज्य उन्हें सहायता देने में भेदभाव नहीं करेगा?
  - **अनुच्छेद 30**
- अनुच्छेद 31 में किस अधिकार का उल्लेख था, जिसे 1978 में निरसित कर दिया गया?
  - **सम्पत्ति का अधिकार**
- 44वें संविधान संशोधन द्वारा सम्पत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर अब किस प्रकार का अधिकार बनाया गया है? - **कानूनी अधिकार**
- किन अनुच्छेदों का उद्देश्य जर्मीदारी प्रथा का उन्मूलन करना है, जिससे भूमि सुधारों को लागू किया जा सके?
  - **अनुच्छेद 31 'क' एवं 'ख'**
- किस अनुच्छेद के अनुसार यदि राज्य किसी सम्पदा या उससे सबंधित किन्हीं अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है तो सर्वोच्च न्यायालय में इस आधार पर अपील नहीं की जा सकती कि इससे अनुच्छेद 14 तथा 19 का उल्लंघन होता है। किंतु राज्य का विधानमंडल यदि इन उपबंधों को प्राप्त करना चाहता है, तो यह आवश्यक है कि राष्ट्रपति की अनुमति ली जाये?
  - **अनुच्छेद 31 'क'**
- कौन-सा अनुच्छेद यह उपबंध करता है कि यदि अनुसूची 9 में किन्हीं नियमों या विनियमों को डाल दिया जाता है, तो सर्वोच्च न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि इसके प्रावधान अनुच्छेद 14 और 19 का अतिक्रमण करते हैं? - **अनुच्छेद 31 'ख'**
- अनुच्छेद 31 'क' एवं 'ख' को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया?
  - **42वें संविधान संशोधन द्वारा**
- मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट कहां दायर की जा सकती है?
  - **सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में**
- सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। उच्च न्यायालय को यह अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है?
  - **अनुच्छेद 226**
- रिट के अधिकार के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में से किसका न्यायिक क्षेत्र बड़ा है?
  - **उच्च न्यायालय का**
- संविधान को अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? - **संवैधानिक उपचारों का अधिकार**
- मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय कौन-से आदेश जारी करता है?
  - **बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिपेध, उत्प्रेषण और अधिकार पृच्छा**
- अनुच्छेद 32 (संविधानिक उपचारों का अधिकार) के महत्व को देखते हुए किसने इसे 'संविधान की आन्तर्मा तथा हृदय' कहा था? - **डॉ. भीमराव अम्बेडकर** ने भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किये गये हैं?
  - **संवैधानिक उपचारों का अधिकार**
- Habeas Corpus (बंदी प्रत्यक्षीकरण) लैटिन भाषा का शब्द है। इसका क्या तात्पर्य होता है?
  - **संवैधानिक उपचारों का अधिकार**
- कौन-सी रिट याचिका आपातकाल में भी निलम्बित नहीं होती है? - **बंदी प्रत्यक्षीकरण**

**उत्प्रेषण प्रलेख (Writ of Certiorari):**  
यह रिट उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय अथवा प्राधिकरण को उसमें विचाराधीन किसी मामले से संबंधित अभिलेखों को उच्च न्यायालय में विचार करने हेतु भेजने का आदेश है। यह उस समय जारी किया जाता है, जब कोई निम्न न्यायालय अथवा प्राधिकरण के बिना अपने क्षेत्राधिकार से अधिक अथवा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध कार्य कर रहा हो या अपने नियत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इंकार कर रहा हो। इस रिट का प्रयोग उस समय किया जाता है, जब निम्न न्यायालय ने किसी मामले की सुनवाई करके अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करते हुए निर्णय दे दिया हो। ऐसी दशा में वह निर्णय निरस्त हो जाता है।

**प्रतिषेध प्रलेख (Writ of Prohibition):**  
यह प्रलेख भी किसी उच्च न्यायालय के द्वारा किसी निम्न अथवा प्राधिकरण संस्था को अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर स्वयं करने अथवा बिना क्षेत्राधिकार के कार्य करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। उत्प्रेषण प्रलेख और प्रतिषेध प्रलेख में अंतर यह है कि प्रतिषेध प्रलेख उस समय जारी किया जाता है, जब न्यायालय के समक्ष किसी ऐसे मामले की कार्यवाही लम्बित हो, जिसकी सुनवाई करने का उसे अधिकार नहीं है। इस रिट के जारी करने का उद्देश्य न्यायालय को उस मामले में कार्यवाही करने से रोकना होता है। उत्प्रेषण प्रलेख उस समय जारी किया जाता है, जब किसी मामले में निम्न न्यायालय ने निर्णय दे दिया हो। इस प्रलेख के जारी होने के बाद वह मामला निम्न न्यायालय से उच्च न्यायालय भेज दिया जाता है और निम्न न्यायालय यदि निर्णय दे चुका है तो वह निर्णय निरस्त हो जाता है।

**अधिकार पृच्छा प्रलेख (Writ of Quo-Warranto):** यह एक व्यक्ति को कोई ऐसा सार्वजनिक पद ग्रहण करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है, जिस पद को ग्रहण करने का वह अधिकारी नहीं है।

## मौलिक अधिकार, नीति निवेशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य

- किस आदेश के तहत न्यायालय किसी अधिकारी को जिसने किसी व्यक्ति को अवैध ढंग से बंदी बना रखा हो, आज्ञा दे सकता है कि बंदी को (24 घंटे के अंदर) उपस्थित किया जाये ताकि उसकी गिरफ्तारी के औचित्य का निर्णय किया जा सके? - **बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत**
- किस स्थिति में 'बंदी प्रत्यक्षीकरण' रिट जारी की जाती है? - **दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी मैंडेमस (Mandamus) का शाब्दिक अर्थ क्या है?** - **आज्ञा देना (परमादेश)**
- किस आदेश के तहत न्यायालय द्वारा किसी अधिकारी, संस्था अथवा निम्न न्यायालय को अपने कर्तव्यों के पालन के लिए आदेश दिया जाता है? - **परमादेश परमादेश रिट किन व्यक्तियों के प्रति जारी नहीं की जा सकती है?** - **निर्जी व्यक्तियों परमादेश रिट और किनके प्रति जारी नहीं जी का सकती?**
- **- राष्ट्रपति, राज्यपाल, हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट तथा संसद के प्रति कौन-सी दो रिटें हैं जो अधीनस्थ न्यायालयों के प्रति जारी की जाती हैं?** - **प्रतिपेध एवं उत्प्रेषण**
- किस आदेश के तहत किसी निम्न न्यायालय के अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने के लिए उससे स्पष्टीकरण मांगा जाता है और यह प्रतिपेध से इस अर्थ में अलग है कि इसे कार्य होने के पश्चात जारी किया जाता है? - **उत्प्रेषण (Certiorari)**
- किस आदेश के तहत सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय अवर न्यायालयों से प्रलेख मांगा सकता है? - **उत्प्रेषण**
- किस आदेश के तहत किसी निम्न न्यायालय को आदेश दिया जाता है कि वह उस कार्य को, जो उसके अधिकार क्षेत्र के बाहर है, न करे? - **प्रतिपेध (Prohibition)**
- जब कोई व्यक्ति बिना किसी अधिकार के किसी लोक पद को धारण किये रहता है, तो कौन-सा रिट जारी करके उससे पूछा जाता है कि वह किस अधिकार से उस पद को धारण किये हुए है? - **अधिकार पृच्छा रिट (Writ of Quo-Warranto)**
- किस संविधान संशोधन द्वारा एक नया अनुच्छेद 32ए का अंतःस्थापन करके यह व्यवस्था की गयी थी कि अनुच्छेद 32 के अधीन कार्यवाहियों में राज्य विधियों की संवैधानिक वैधता पर उच्चतम न्यायालय में उस समय तक विचार नहीं किया जायेगा, जब तक कि किसी केंद्रीय विधि की संवैधानिक वैधता भी ऐसी कार्यवाहियों में प्रश्नगत न हो? - **42वा संविधान संशोधन अधिनियम**
- सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि अनुच्छेद 32 द्वारा दी गयी न्यायिक पुर्विलोकन की शक्ति संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। क्या इसे संविधान संशोधन के द्वारा नष्ट नहीं किया जा सकता है? - **नहीं**
- किस अनुच्छेद के माध्यम से संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी अन्य न्यायालय को भी रिटों को जारी करने का अधिकार दे सकती है। हालांकि संसद ने अभी तक ऐसा नहीं किया है? - **अनुच्छेद 32(3)**
- कौन-से सिद्धांत के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने यह अधिनिर्धारित किया है कि संसद जब कोई अधिनियम पारित करती है, तो उसका वही उतना ही भाग अवैध होगा जितना कि वह मौलिक अधिकारों से असंगत है? - **पृथक्करण का सिद्धांत**
- कोई भी व्यक्ति संविधान में दिये गये अधिकारों का परित्याग नहीं कर सकता। ऐसा न करने के पीछे क्या कारण है? - **व्यक्ति के अधिकारों तथा कर्तव्यों में सामंजस्य स्थापित किया जा सके**
- किस सिद्धांत के अनुसार, संविधान के निर्माण के पूर्व विधि वहां तक अप्रभावी होगी या शून्य होगी, जहां तक वह संविधान की विधियों से असंगत है? - **आच्छादन का सिद्धांत**
- किस अनुच्छेद के अनुसार संसद विधि द्वारा सशस्त्र बलों को सदस्यों, लोक व्यवस्था बनाये रखने वाले बलों के सदस्यों तथा कुछ अन्य व्यक्तियों के इन अधिकारों को लागू होने की सीमाओं अथवा मर्यादाओं का निर्धारण कर सकती है, ऐसा करने के पीछे उद्देश्य यह है कि वे अपना कर्तव्य उचित तरीके से निभा सके और उनमें अनुशासन बना रहे? - **अनुच्छेद 33**

ऐसी नियंत्रण जारी करते हुए न्यायालय उस पद को उस समय तक रिव घोषित कर सकता है, जब तक न्यायालय द्वारा उसका निर्णय न हो जाये।

### मीसा, 1971

आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम (मीसा), 1971 में पारित इस अधिनियम के अंतर्गत नजरबंदी की अधिकतम अवैध एक वर्ष थी तथा व्यक्ति को परामर्शदाता प्रदाता से सलाह प्राप्त किये बिना संकट काल की अवैध में अधिक से अधिक 21 माह तक नजरबंद रखा जा सकता है, **मीसा** मह अधिनियम 44वें संविधान संशोधन के प्रतिकूल था। इस कारण अप्रैल 1979 में यह स्वतः ही समाप्त हो गया।

### राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980

राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (National Security Act) को संक्षेप में रासुका या एनएसए कहा जाता है। 23 सितंबर, 1980 को इंदिरा गांधी की सरकार के दौरान इसे बनाया गया। इसका उद्देश्य साम्राज्यिक और जातीय दंगों और देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक अन्य गतिविधियों के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को निरुद्ध करना है। यह कानून देश की सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेने की शक्ति देता है। यदि सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में उसके सामने बाधा खड़ी कर रहा है तो वह उसे हिरासत में लेने का आदेश दे सकती है। इस कानून का इस्तेमाल जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, राज्य सरकार अपने सीमित दायरे में भी कर सकती है। इसमें हिरासत में लिये गये व्यक्ति को अधिकतम एक वर्ष तक जेल में रखा जा सकता है। **रासुका** के तहत हिरासत में लिये गये व्यक्ति को उनके खिलाफ आरोप तय किये बिना 10 दिनों के लिए रखा जा सकता है। **हिरासत** में लिया गया

■ किस अनुच्छेद के अधीन संसद विधि द्वारा मार्शल लॉ के प्रवर्तन के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करके किये गये किसी कार्य के लिए किसी व्यक्ति की क्षतिपूर्ति कर सकती है? - **अनुच्छेद 34**

■ किस अनुच्छेद के तहत संसद को यह शक्ति होगी कि वह जिन विषयों के लिए अनुच्छेद 16(3), 32(3), 33 और 34 के अधीन संसद विधि द्वारा उपबंध कर सकेगी? - **अनुच्छेद 35**

■ भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है? - **अनुच्छेद 226**

■ मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में शामिल किये जाने की वकालत किस रिपोर्ट में की गयी थी? - **नेहरू रिपोर्ट 1928**

■ भारतीय संविधान के अनुसार समानता के मूलभूत अधिकार में क्या शामिल नहीं है? - **आर्थिक समानता का अधिकार**

■ 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सम्पूर्ण मौलिक अधिकारों को आपातकाल में निम्न किया जा सकता था, परंतु किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा ~~अनुच्छेद 20~~ एवं 21 में दिये गये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है? - **42वें संविधान संशोधन द्वारा**

■ किस संशोधन के अनुसार 'वी' तथा 'सी' में उल्लिखित निदेश तत्वों के कार्यान्वयन के लिए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने पर भी परिवर्तन को चुनौती नहीं दी जा सकती है? - **25वां संशोधन**

■ किसने कहा था, "मूल अधिकारों की रक्षा कानून द्वारा नहीं, अपितु सतत जागरूक जनमत द्वारा होती है"? - **एम.वी. पायली**

■ भारतीय दंड सहिता (आईपीसी) की किस धारा में मानहानि की परिभाषा दी गयी है, जिसके अनुसार किसी व्यक्ति को घृणा, मजाक या तिरस्कार का पात्र बनाकर पेश करना मानहानि है? - **धारा 499**

(न्यायालयों ने आईपीसी की धारा 499 को संवैधानिक दृष्टि से विधिमान्य ठहराया है।)

### राज्य के नीति निदेशक तत्व

■ भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख पाया जाता है? - **अनुच्छेद 36 से 51 तक**

■ नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? - **भाग 4 में**

■ संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? - **कल्याणकारी राज्य के रास्ते आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना**

■ संविधान में नीति निदेशक तत्वों को किस संविधान से ग्रहण किया गया है? - **आयरलैंड के संविधान से**

■ नीति निदेशक तत्वों को किसने भारतीय संविधान की 'एक अनोखी एवं महत्वपूर्ण विशेषता' कहा है? - **डॉ. वीआर अम्बेडकर ने**

■ राज्य के नीति निदेशक तत्व किनके लिए निर्देश है कि इनके अनुसार सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था का संचालन करेंगे? - **राज्यों के प्रति**

■ किसने कहा था कि "जहां मौलिक अधिकारों और निदेशक तत्वों में विरोध हो, वहां निदेशक तत्वों को वरीयता दी जानी चाहिए"? - **जवाहरलाल नेहरू**

■ किस अनुच्छेद के तहत राज्य का यह दायित्व बताया गया है कि वह सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय से युक्त एक समाज व्यवस्था का विकास करते हुए लोगों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करे? - **अनुच्छेद 38 के तहत**

व्यक्ति उच्च न्यायालय के सलाहकार बोर्ड के समक्ष अपील कर सकता है, लेकिन उसे मुकदमे के दौरान वकील रखने की अनुमति नहीं होती।

### टाइम 1985

आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिविधि (निरोधक) अधिनियम, 1985 (Terrorist and Disruptive Activities (Prevention) Act) भारत में बढ़ रहे आतंकवाद पर नियंत्रण के लिए इस अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार पुलिस अभियुक्त को 180 दिनों तक हिरासत में रख सकती है। एलिम्य के साथ की गयी अपार्टमेंट रेफिनीटि को सबूत माना जा सकता है तथा इसे एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित किया जा सकता है। अभियुक्त को आरोपी और गवाहों की जानकारी से वर्चित रखा जा सकता है। इसके लिए अपील मात्र 30 दिनों के भीतर केवल उच्चतम न्यायालय में की जा सकती है। 1995 में दमकी अतिविरोधी समाज हो गयी।

### भाग-4

## राज्य की नीति के निर्देशक तत्व

### (अनुच्छेद 36-51)

- **अनुच्छेद 36:** परिभाषा
- **अनुच्छेद 37:** इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना
- **अनुच्छेद 38:** राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनायेगा।
- **अनुच्छेद 39:** राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निदेशक तत्व
- **अनुच्छेद 39क:** समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता
- **अनुच्छेद 40:** ग्राम पंचायतों का संगठन
- **अनुच्छेद 41:** कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार
- **अनुच्छेद 42:** काम की न्यायसंगत और मानवोंचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध

## मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य

किसने कहा था कि "हम निदेशक तत्वों की क्रियान्वित के लिए दृढ़ संकल्प हैं और इसके लिए यदि हमें मौलिक अधिकारों में संशोधन भी करना पड़े तो करेंगे"? - इविगा गांधी नीति निदेशक सिद्धांतों को वर्णीकृत किया जा सकता है?

- आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक च अंतराष्ट्रीय सिद्धांत में "नीति निदेशक तत्व भारतीय प्रशासकों के आचरण का सिद्धांत है।" यह कथन किसका है?

किसके अनुसार, "भारतीय संविधान का यह भाग (4) फेब्रियन समाजवाद की स्थापना करता है"? - आइवर जेनिंगम

मौलिक अधिकार व्यक्तिनिष्ठ हैं, जबकि निदेशक सिद्धांत? - मपार्जनिष्ठ है

किस मामले में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों एवं नीति निदेशक तत्वों के मध्य सर्वोच्चता को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था? - चंपक दोगाइजन बनाम मदाम गन्य में

संविधान में वर्णित राज्य के नीति निदेशक तत्व लोक कल्याण से प्रत्यक्षतः जुड़े हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में कहा कि निदेशक तत्व 'वादयोग्य' नहीं हैं, जबकि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय लेख और आदेश जारी कर सकते हैं?

- चंपकम दोगाइजन वाद में

किस मामले में न्यायालय ने कहा कि मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं? - चंद्रभवन बोर्डिंग और लॉजिंग मामले में

किसके अनुसार, "यह एक ऐसा चेक है, जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर छोड़ दिया गया है"? - कंटी. शाह

गोलकनाथ विवाद 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता दी, परंतु इंदिरा सरकार ने किन संवैधानिक संशोधनों के द्वारा नीति निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी? - 24वें एवं 25वें संवैधानिक संशोधन द्वारा

मौलिक अधिकारों एवं नीति निदेशक सिद्धांतों के बीच विवाद किस मामले से समाप्त हो गया?

- मिनर्वा मिल्स विवाद से

किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि मौलिक अधिकार एवं नीति निदेशक तत्व दोनों ही संविधान के अभिन्न अंग हैं एवं एक-दूसरे के पूरक हैं?

- मिनर्वा मिल्स बनाम भारत मध्य विवाद-1980

सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में यह अभिन्नात्मकता किया कि समान कार्य के लिए समान वेतन एक मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि निदेशक तत्व है, लेकिन यह एक संवैधानिक प्रावधान है, इसलिए यदि राज्य समान कार्य के लिए विभेदपूर्ण वेतन देता है तो न्यायालय उनमें हस्तक्षेप करेगा? - रणधीर बनाम भारत मध्य 1982

किस अनुच्छेद में यह उपबंध है कि नीति निदेशक तत्वों को किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं कराया जा सकता है?

- अनुच्छेद 37 में

राज्य के नीति निदेशक तत्व को सामाजिक क्रांति का दस्तावेज भी कहा जाता है। संविधान का कौन-सा अनुच्छेद इसकी ओर इंगित करता है? - अनुच्छेद 38

कौन-सा अनुच्छेद समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराता है?

- अनुच्छेद 39'क'

नीति निदेशक के किन अनुच्छेदों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गयी है?

- अनुच्छेद 39'ख' एवं 'ग'

लोक अदालतें, एक ऐसी संवैधानिक फोरम हैं, जिनकी स्थापना समाज के वंचित एवं गरीब तबकों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता देने के लिए की गयी। इन्हें विधिक शक्ति संविधान के किस भाग से प्राप्त होती है?

- राज्य की नीति के निदेशक तत्व (अनुच्छेद 39क)

किस अनुच्छेद में समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण का उद्देश्य सामूहिक हित के सर्वोत्तम रूप से क्रियान्वित करना है? - अनुच्छेद 39'ख'

- अनुच्छेद 43: कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि
- अनुच्छेद 43क: उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों का भागलेना
- अनुच्छेद 44: नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता
- अनुच्छेद 45: बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध
- अनुच्छेद 46: अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल बर्गों के शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि
- अनुच्छेद 47: पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य
- अनुच्छेद 48: कृषि और पशुपालन का संगठन
- अनुच्छेद 48क: पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्द्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा
- अनुच्छेद 49: राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण
- अनुच्छेद 50: कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण
- अनुच्छेद 51: अंतराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि

### आतंक निरोधक अध्यादेश (पोटा)

1995 में टाडा की समाप्ति के बाद आतंकवाद के निवारण के लिए अप्रैल 2002 में आतंकवादी गतिविधि रोकथाम कानून (POTO: Prevention of Terrorism Act) बनाया गया। इस कानून में भी कड़े प्रावधान किये गये थे। इसके तहत ऐसी कोई भी कार्रवाई जिसमें हथियारों या विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ हो अथवा जिसमें किसी की मौत हो जाये या कोई घायल हो जाये आतंकवादी कार्रवाई मानी जाती थी। इनके अलावा ऐसी कोई भी गतिविधि जिससे किसी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा हो या सरकारी सेवाओं में बाधा आई हो या फिर उससे देश की

## विज्ञापन NCERT भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान सार संग्रह (By : Khan Sir, Patna)

- किस अनुच्छेद में धन और उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण को निपिद्ध किया गया है? - **अनुच्छेद 39'ग'**
- 'समान कार्य के लिए समान वेतन' का प्रावधान राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के तहत किस अनुच्छेद में किया गया है? - **अनुच्छेद 39'घ'**
- बच्चों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं देने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? - **अनुच्छेद 39'च'**
- किस अनुच्छेद के तहत स्वशासन की इकाइयों के रूप में ग्राम पंचायतों को संगठित करना राज्य का कर्तव्य बताया गया है? - **अनुच्छेद 40 के तहत**
- कौन-सा अनुच्छेद महात्मा गांधी के **ग्राम स्वराज्य** को अपनाने की स्वीकृति देता है? - **अनुच्छेद 40**
- किस अनुच्छेद के द्वारा लोगों के लिए काम, पर्याप्त मजदूरी एवं बेरोजगारी, वृद्धावस्था सहायता की स्थिति में लोक सहायता के अधिकार को राज्य द्वारा सुनिश्चित करने को निर्देशित किया गया है? - **अनुच्छेद 41**
- किस अनुच्छेद के द्वारा राज्य को कार्य की मानवीय स्थितियों एवं स्त्रियों की प्रसूति सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं? - **अनुच्छेद 42**
- किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य कर्मकारों के लिए काम, निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसर उपलब्ध करायेगा और गावों में कुटीर उद्योग को बढ़ाने का प्रयास करेगा? - **अनुच्छेद 43**
- किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्य विधि द्वारा उद्योगों के प्रवंध में कर्मकारों की भागीदारी को सुनिश्चित करने की व्यवस्था करेगा? - **अनुच्छेद 43'क'**
- किस अनुच्छेद के तहत राज्य भारत के समस्त नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) लागू करने का प्रयास करेगा? - **अनुच्छेद 44**
- अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए राज्य को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रवंध करने का निर्देश था, परंतु यह निर्देश 86वें संविधान संशोधन के बाद कितने वर्ष के बच्चों तक रह गया है? - **0 से 6 वर्ष तक के**
- किस अनुच्छेद के तहत राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करेगा? - **अनुच्छेद 46**
- यह किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्य नागरिकों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए प्रयास करेगा? - **अनुच्छेद 47**
- अनुच्छेद 47 किस प्रकार के द्रव्यों के प्रयोग का नियंत्रण भी करता है? - **मादक द्रव्य**
- किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशिष्ट तथा गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधाल एवं वाहक पशुओं की नस्लों में सुधार के लिए और उनके वध का प्रतिपेध करने के लिए प्रयत्न करेगा? - **अनुच्छेद 48 में**
- किस अनुच्छेद के तहत राज्य पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्द्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा? - **अनुच्छेद 48'क'**
- नीति निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 39क, 43क, 48क किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जाड़े गये? - **42वें संविधान संशोधन द्वारा**
- किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रीय महत्व के घोषित स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं के संरक्षण के लिए राज्य अनिवार्य रूप से कार्य करेगा? - **अनुच्छेद 49 में**
- किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य, लोक सेवाओं में कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करने के लिए प्रयास करेगा? - **अनुच्छेद 50 के अनुसार**

एकता और अखंडता को खतरा हो, वह भी इसी श्रेणी में आती थी। पोटा के तहत गिरफ्तारी के बाल शक के आधार पर की जा सकती थी। इस कानून में पुलिस को यह भी अधिकार दिया गया था कि वह बिना वारंट के किसी की भी तलाशी ले सकती थी और टेलीफोन तथा अन्य संचार सुविधाओं पर नजर रखने का प्रावधान भी इस कानून में था। इसमें अभियुक्त की जमानत को कठिन बनाया गया। पुलिस किसी भी संगठन को आसानी से आतंकवादी संगठन कहते हुए उसे प्रतिवर्धित कर सकती थी। 23 अक्टूबर, 2004 को इस कानून को निरस्त कर दिया गया।

### ग्राम स्वराज

स्वराज का तात्पर्य है स्व-राज (Self-rule) और आत्मसंयम (Self-restraint)। ग्राम-स्वराज का शाब्दिक अर्थ है 'गांव का अपना शासन'। इसमें एक गांव का पूरी तरह से गणतंत्र और अपनी जरूरतों के लिए पड़ोसियों से स्वतंत्र होना शामिल है। गांधीजी ने स्वदेशी और हाथ से बने औद्योगिक उत्पादों को गांवों में बनाने की वकालत की थी। उन्होंने 'बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं, जनसाधारण के द्वारा उत्पादन' का नारा दिया था। भारत के आर्थिक विकास के नजरिए से ग्राम स्वराज गांधीजी की विचारधारा के केंद्र में था। गांधीजी का मानना था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। इसलिए उनकी ग्राम स्वराज की परिकल्पना में गांवों की स्वायत्त एवं स्वालंबी आर्थिक एवं प्रबंधन सत्ता केंद्र में थी। उनकी दृष्टि में गांवों की सम्पन्नता में ही देश की सम्पन्नता तथा गांवों की स्वायत्त पंचायती व्यवस्था में ही देश की सच्ची प्रजातांत्रिक छवि अभिव्यक्ति पा सकती है। हिंद स्वराज की परिकल्पना को उन्होंने ग्राम स्वराज का पर्याय बना दिया। गांधीजी के सपनों के ग्राम स्वराज की अवधारणा को

## मौलिक अधिकार, नीति निदेशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य

राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को उन्नति का, अंतर्राष्ट्रीय सधियों व अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का आदर तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा हल करने का प्रयास करेगा। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? - **अनुच्छेद 51 में**

मौलिक अधिकार नकारात्मक निषेध आज्ञाएं हैं, जो राज्य की शक्ति पर अंकुशलगत हैं, जबकि नीति निदेशक तत्व सकारात्मक आदेश हैं, जो यह बतलाते हैं कि राज्य को क्या करना है। अगर मौलिक अधिकार 'राजनीतिक लोकतंत्र' की स्थापना करते हैं तो नीति निदेशक तत्वों द्वारा उस स्थापित किया जाता है? - **उत्तरिया और नीतिवाचक तत्वों**

संवैधानिक दर्जा देकर शासन ने सामाजिक न्याय का पथ प्रशस्त किया है। यह व्यवस्था समानता के आधार पर सामाजिक न्याय व उत्थान का मूल स्रोत भी है। भारतीय संविधान के भाग-4 में अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम स्वराज के तहत ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख किया गया है।

### मौलिक कर्तव्य

■ मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में शामिल किया गया? - **सरदार म्हणे मिह समिति**

■ मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद एवं भाग में शामिल किया गया? - **अनुच्छेद 51(क) एवं भाग 4(क) में**

■ मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित (लिया गया) है? - **पूर्व सोवियत सघ के संविधान से**

■ मौलिक कर्तव्यों को कब संविधान में शामिल किया गया और किस संविधान संशोधन के द्वारा? - **1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा**

■ 42वां संविधान संशोधन किस प्रधानमंत्री के समय पारित किया गया था? - **श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में**

■ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51(क) में 10 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया था। 86वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गयी है? - **कुल 11**

■ क्या मौलिक कर्तव्यों को न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय कराया जा सकता है? - **नहीं**

■ मौलिक कर्तव्य न्यायपालिका द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, लेकिन क्या इनका जान-बूझ कर उल्लंघन करने पर किसी व्यक्ति को दंड दिया जा सकता है? - **हाँ**

■ यह किसका कथन है कि "यदि हम लोग मौलिक कर्तव्यों को अपने दिमाग में रख लें, तो हम तुरंत ही शांतिपूर्ण एवं मैत्रीपूर्ण क्रांति देखेंगे"? - **श्रीमती इंदिरा गांधी**

■ मौलिक कर्तव्यों में किस प्रकार के पर्यावरण की रक्षा करने और उसका संवर्द्धन करने की चर्चा की गयी है? - **प्राकृतिक पर्यावरण की**

■ प्रत्येक माता-पिता या संरक्षक को 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करने के कर्तव्य का निर्धारण किस संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया है? - **86वें संविधान संशोधन द्वारा**

■ वर्ष 1999 में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित किस समिति का गठन किया गया?

- **वर्मा समिति**

■ 30 नवंबर, 2016 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक अंतर्रिम आदेश में कहा था कि देशभर के सभी सिनेमाघरों में फ़िल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान 'जन गण मन' बजाना अनिवार्य है। किस तिथि को अपने फैसले में न्यायालय ने केंद्र सरकार से कहा कि सिनेमाघरों और अन्य जगहों पर राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य हो या नहीं यह सरकार तय करे? - **23 अक्टूबर 2017 को**

■ मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया है। इसका क्या प्रयोजना है?

- **विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना**

■ वैज्ञानिक सोच और जांच की भावना का विकास करना भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल है?

- **मौलिक कर्तव्य**

### समान नागरिक संहिता

भारतीय संविधान के भाग-4 में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 44 के अनुसार भारत के समस्त नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता होगी। इसका व्यावहारिक अर्थ है कि भारत के सभी धर्मों के नागरिकों के लिए एक समान धर्मनिरपेक्ष कानून होना चाहिए। संविधान निर्माताओं ने राज्य के नीति निदेशक तत्व के माध्यम से इसको लागू करने को जिम्मेदारी बाद की सरकारों को सौंपी थी। समान नागरिकता संहिता के अंतर्गत व्यक्तिगत कानून, संपत्ति संबंधी कानून और विवाह, तलाक तथा गोद लेने से संबंधित कानूनों में मतभिन्नता है। भारत में अधिकतर व्यक्तिगत कानून धर्म के आधार पर तय किये गये हैं। हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्मों के व्यक्तिगत कानून हिंदू विधि से संचालित किये जाते हैं, जबकि मुस्लिम तथा ईसाई धर्मों के अपने अलग व्यक्तिगत कानून हैं। मुस्लिमों का कानून शरीअत पर आधारित है, जबकि अन्य धार्मिक समुदायों के व्यक्तिगत कानून भारतीय संसद द्वारा बनाये गये कानून पर आधारित हैं। अब तक गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर समान नागरिक संहिता लागू है। सुप्रीम कोर्ट ने 13 सितंबर, 2019 को एक फैसले में कहा कि देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए अभी तक कोई प्रयास नहीं किया गया है।

## भारतीय संसद

- भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? - **संसद (Parliament)**
- भारतीय संविधान की संसदीय व्यवस्था किस संविधान से ली गयी है? - **ब्रिटिश मॉडल**
- भारत में द्विसदनीय व्यवस्थापिका किस अधिनियम द्वारा अपनाया गया था?
  - **भारत सरकार अधिनियम, 1919** द्वारा
- किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारतीय संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों (लोकसभा + राज्यसभा) से मिलकर बनेगी? - **अनुच्छेद 79** में
- राज्यसभा को पहले राज्य परिषद एवं लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता था। लोकसभा एवं राज्यसभा को यह नाम किस वर्ष दिया गया? - **वर्ष 1954** में
- संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? - **लोकसभा** को
- संसद के किस सदन को स्थायी सदन कहा जाता है? - **राज्यसभा** को
- संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के गठन का उल्लेख है? - **अनुच्छेद 80** में
- अनुच्छेद 80(1) के अनुसार, **राज्यसभा** में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? - **250**
- राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से राज्यसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्यों का चुनाव किया जा सकता है? - **238**
- राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? - **12** सदस्यों को
- अनुच्छेद 80(3) के अनुसार, राज्यसभा के 12 सदस्यों का मनोनयन किन क्षेत्रों से होता है? - **साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा**
- अनुच्छेद 80(2) के अनुसार, राज्यसभा में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के सीटों का आवंटन संविधान की किस अनुसूची में वर्णित है? - **चौथी अनुसूची**
- अनुच्छेद 80(4) के अनुसार, राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। इसके चुनाव में कौन भाग लेता है? - **राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य**
- प्रति दो वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्यों की सदस्यता समाप्त होती रहती है? - **एक तिहाई**
- राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस पर निर्भर करता है? - **राज्य की जनसंख्या पर**
- राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक (31) है? - **उत्तर प्रदेश की**
- राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? - **6 वर्ष**
- राज्यसभा का गठन पहली बार 3 अप्रैल, 1952 को हुआ था। इसकी प्रथम बैठक कब हुई थी? - **13 मई, 1952** को
- राज्यसभा की दो बैठकों के मध्य अधिकतम अंतर कितने महीने का हो सकता है? - **6 माह का**
- राज्यसभा एक स्थायी सदन है, किंतु इसके एक-तिहाई सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? - **30 वर्ष**
- वह कौन-सा सदन है, जिसकी अध्यक्षता उस सदन का सदस्य नहीं करता है? - **राज्यसभा**
- अनुच्छेद 89(1) के तहत राज्यसभा का पदन सभापति कौन होता है? - **उपराष्ट्रपति**
- राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव कौन थीं? - **वी.एस. रमादेवी**
- राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है? - **उपसभापति**

## अध्याय 2

## संसद (अनुच्छेद 79-122)

## साधारण (General) (अनुच्छेद 79-88)

- **अनुच्छेद 79:** संसद का गठन
- **अनुच्छेद 80:** राज्यसभा की संरचना
- **अनुच्छेद 81:** लोकसभा की संरचना
- **अनुच्छेद 82:** प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनःसमायोजन
- **अनुच्छेद 83:** संसद के सदनों का अवधि
- **अनुच्छेद 84:** संसद की सदस्यता के लिए अर्हता
- **अनुच्छेद 85:** संसद के सत्र, सत्रावधान और विघटन
- **अनुच्छेद 86:** सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार
- **अनुच्छेद 87:** राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण
- **अनुच्छेद 88:** सदनों के बारे में मत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार

## संसद के अधिकारी (अनुच्छेद 89-98)

- **अनुच्छेद 89:** राज्यसभा का सभापति और उपसभापति
- **अनुच्छेद 90:** उपसभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना
- **अनुच्छेद 91:** सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति
- **अनुच्छेद 92:** जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कानून संकल्प विचाराधीन है, तब उनकी पीठासीन नहोना
- **अनुच्छेद 93:** लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष
- **अनुच्छेद 94:** अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना
- **अनुच्छेद 95:** अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति

## भारतीय संसद

- राज्यसभा के उपसभापति को पद से हटाने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित होना चाहिए? - समस्त सदस्यों के बहुमत में भारत के किन पांच केन्द्रशासित प्रदेशों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है?
  - अंडमान व निकोबार, चंडीगढ़, लक्ष्मीपुर, लहाना और दादरा व नगर हवेली तथा दमन व दीवार
- भारत के कौन-से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे थे?
  - इंदिगा गांधी एवं मनमोहन सिंह
- भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी धन खर्च नहीं किया जा सकता है? - संसद राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष जबकि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है? - प्रत्यक्ष
- भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा का गठन होता है?
  - अनुच्छेद 81 के अंतर्गत
- लोकसभा को और किन नामों से संबोधित किया जाता है?
  - निम्न सदन, प्रथम मदन एवं लोकप्रिय मदन
- लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? - 552 सदस्य
  - [नोट: लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य (530 राज्य, 20 केन्द्रशासित प्रदेश, 2 एंग्लो-इंडियन) हो सकते हैं। वर्तमान में, सदन की शक्ति 545 है, जिसमें 530 सदस्य राज्यों से, 13 केन्द्रशासित प्रदेशों से और 2 राष्ट्रपति द्वारा नामित एंग्लो-इंडियन समुदाय से हैं।]
- राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में नामित कर सकता है? - दो
- अनुच्छेद 81(1ख) के मुताबिक संघ राज्य क्षेत्रों से लोकसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित हो सकते हैं? - 20 सदस्य
- वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस आधारित है?
  - 1971 की जनगणना पर
- लोकसभा के सदस्यों की संख्या कब तक नहीं बढ़ायी जा सकती है? - 2026 तक
- लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कितने वर्षों के लिए जनता द्वारा किया जाता है?
  - 5 वर्ष के लिए
- लोकसभा चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। मतदाता के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गयी है? - 18 वर्ष
- अनुच्छेद 84(ख) के अनुसार, लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? - 25 वर्ष
- लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को भारत के किसी भी चुनाव क्षेत्र से पंजीकृत मतदाता होना जरूरी है। राज्यसभा का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को सामान्यतः किस राज्य का निवासी होना चाहिए?
  - उस राज्य का, जिस राज्य से वह चुनाव लड़ना चाहता है
- संसद के किसी सदन के सदस्य की योग्यता तथा अयोग्यता का निर्धारण कौन करता है?
  - राष्ट्रपति, चुनाव आयोग के परामर्श से
- संसद में कौन-सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि (लोकसभा में 80 और राज्यसभा में 31) भेजता है?
  - उत्तर प्रदेश
- उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र (लोकसभा) किस राज्य में है?
  - महाराष्ट्र में (48)
- लोकसभा के एक सदस्य के निर्वाचन के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए अर्थात् कितनी जनसंख्या पर लोकसभा के एक सदस्य का निर्वाचन होता है?
  - 10 लाख की जनसंख्या पर
- संसद के सदस्यों के निर्वाचन के लिए योग्यता एवं अयोग्यता का निर्धारण कौन करता है?
  - संसद

- अनुच्छेद 96: जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पाठासीन नहीं होता।
- अनुच्छेद 97: सभापति और उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बीच व व भी
- अनुच्छेद 98: संसद का सचिवालय कार्य मंचालन (अनुच्छेद 99-100)
- अनुच्छेद 99: सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
- अनुच्छेद 100: सदनों में भवान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणनावृत्ति सदस्यों की निरहंताएं (अनुच्छेद 101-104)
- अनुच्छेद 101: स्थानों का रिक्त होना
- अनुच्छेद 102: सदस्यों के लिए निरहंताएं
- अनुच्छेद 103: सदस्यों की निरहंताओं से संबोधित प्रश्नों पर विनिश्चय
- अनुच्छेद 104: अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अहिंत न होते हुए या निर्याहित किये जाने पर बैठने और मत देने के लिए शक्ति
- संसद और उसके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ (अनुच्छेद 105-106)
- अनुच्छेद 105: संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि
- अनुच्छेद 106: सदस्यों के बीच और भी
- विधायी प्रक्रिया (अनुच्छेद 107-111)
- अनुच्छेद 107: विधेयकों के पुनःस्थापन और पारित किये जाने के संबंध में उपबंध
- अनुच्छेद 108: कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
- अनुच्छेद 109: धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया
- अनुच्छेद 110: धन विधेयक को परिभाषा
- अनुच्छेद 111: विधेयकों पर अनुमति वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया (अनुच्छेद 112-117)
- अनुच्छेद 112: वार्षिक वित्तीय विवरण
- अनुच्छेद 113: संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया

## किंतु NCERT भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान सार संग्रह (By : Khan Sir, Patna)

- लोकसभा का नेता कौन होता है? - प्रधानमंत्री
- किस अनुच्छेद के अनुसार, लोकसभा अपने ही सदस्यों में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करती है? - अनुच्छेद 93
- लोकसभा की सभी कार्यवाहियों का संचालन लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा की बैठक को कौन स्थगित करता है? - लोकसभा अध्यक्ष
- लोकसभा अध्यक्ष की स्थिति स्वतंत्र होती है, क्योंकि उसका वेतन एवं भत्ता किस पर भारित होता है? - भारत की संचित निधि
- लोकसभा सदस्यों को प्राप्त अधिकारों तथा विशेषाधिकारों का रक्षक कौन होता है? - लोकसभा अध्यक्ष
- लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कौन सदन की अध्यक्षता करता है और कार्यवाही के नियमानुसार अध्यक्ष के सभी अधिकारों का उपयोग करता है? - लोकसभा उपाध्यक्ष  
(नोट: लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता करने के लिए अध्यक्ष द्वारा 6 सभापति की एक सूची तैयार की जाती है और आवश्यकता पड़ने पर उस सूची में मनोनीत सदस्य सभापति के रूप में सदन की अध्यक्षता करते हैं।)
- लोकसभा अपने किन्हीं दो सदस्यों को एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष के रूप में चुनाव कितने सदस्यों के बहुमत से करती है? - तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से

- अनुच्छेद 114: विनियोग विधेयक
  - अनुच्छेद 115: अनुपूरक, अतिरिक्त अधिक अनुदान
  - अनुच्छेद 116: लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान
  - अनुच्छेद 117: वित्त विधेयकों के बांध में विशेष उपबंध
- साधारणतया प्रक्रिया (अनुच्छेद 118-122)**
- अनुच्छेद 118: प्रक्रिया के नियम
  - अनुच्छेद 119: संसद में वित्तीय कांग संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियम
  - अनुच्छेद 120: संसद में प्रयोग के जाने वाली भाषा
  - अनुच्छेद 121: संसद में चंचा जन निर्बन्धन
  - अनुच्छेद 122: न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाने

### लोकसभा तथा उसके अध्यक्ष

| लोकसभा | प्रथम बैठक       | भूंग            | अध्यक्ष                   | कार्यकाल                              |
|--------|------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 1.     | 13 मई, 1952      | 4 अप्रैल, 1957  | गणेश वासुदेव मावलंकर      | 15 मई, 1952-27 फरवरी, 1956            |
| 2.     | 10 मई, 1957      | 31 मार्च, 1962  | एम. अनंतशयनम आयंगर        | 8 मार्च, 1956-10 मई, 1957             |
| 3.     | 16 अप्रैल, 1962  | 3 मार्च, 1967   | एम. अनंतशयनम आयंगर        | 11 मई, 1957-16 अप्रैल, 1962           |
| 4.     | 16 मार्च, 1967   | 27 दिसंबर, 1970 | सरदार हुकुम सिंह          | 17 अप्रैल, 1962-16 मार्च, 1967        |
| 5.     | 19 मार्च, 1971   | 18 जनवरी, 1977  | नीलम संजीव रेड्डी         | 17 मार्च, 1967-19 जुलाई, 1969         |
| 6.     | 25 मार्च, 1977   | 22 अगस्त, 1979  | सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लो | 8 अगस्त, 1969-17 मार्च, 1971          |
| 7.     | 21 जनवरी, 1980   | 31 दिसंबर, 1984 | सरदार गुरदयाल सिंह ढिल्लो | 22 मार्च, 1971-1 दिसंबर, 1975         |
| 8.     | 15 जनवरी, 1985   | 27 नवंबर, 1989  | बलिराम भगत                | 5 जनवरी, 1976-25 मार्च, 1977          |
| 9.     | 18 दिसंबर, 1989  | 13 मार्च, 1991  | नीलम संजीव रेड्डी         | 26 मार्च, 1977-13 जुलाई, 1977         |
| 10.    | 9 जुलाई, 1991    | 10 मई, 1996     | के.एस. हेगडे              | 21 जुलाई, 1977-21 जनवरी, 1980         |
| 11.    | 22 मई, 1996      | 4 दिसंबर, 1997  | बलिराम जाखड़              | 22 जनवरी, 1980-15 जनवरी, 1985         |
| 12.    | 23 मार्च, 1998   | 26 अप्रैल, 1999 | बलिराम जाखड़              | 16 जनवरी, 1985-18 दिसंबर, 1989        |
| 13.    | 20 अक्टूबर, 1999 | 6 फरवरी, 2004   | रवि राय                   | 19 दिसंबर, 1989-9 जुलाई, 1991         |
| 14.    | 17 मई, 2004      | 18 मई, 2009     | शिवराज वी. पाटिल          | 10 जुलाई, 1991-22 मई, 1996            |
| 15.    | 18 मई, 2009      | 16 मई, 2014     | पी.ए. संगमा               | 23 मई, 1996-23 मार्च, 1998            |
| 16.    | 4 जून, 2014      | 16 जून, 2019    | जी.एम.सी. बालयोगी         | 24 मार्च, 1998-19 अक्टूबर, 1999       |
| 17.    | 17 जून, 2019     | -               | जी.एम.सी. बालयोगी         | 22 अक्टूबर, 1999-3 मार्च, 2002 (निधन) |
|        |                  |                 | मनोहर गजानन जोशी          | 10 मई, 2002-2 जून, 2004               |
|        |                  |                 | सोमनाथ चट्टर्जी           | 4 जून, 2004-31 मई, 2009               |
|        |                  |                 | मीरा कुमार                | 1 जून, 2009 से 4 जून, 2014            |
|        |                  |                 | सुमित्रा महाजन            | 5 जून, 2014 से 16 जून, 2019           |
|        |                  |                 | ओम बिरला                  | 19 जून, 2019 से अब तक                 |

## भारतीय संसद

■ यदि लोकसभा अध्यक्ष की लोकसभा सदस्यता चली जाती है तो वह उस पद पर नहीं रहता, लेकिन वह त्यागपत्र देकर भी अपने पद से मुक्त हो सकता है। वह अपना त्यागपत्र किसको देता है?

- लोकसभा उपाध्यक्ष को

■ लोकसभा अध्यक्ष सामान्यतः सदन के जीवनकाल पर्यंत तक पद धारण करता है। लेकिन उसका पद किस आधार पर पहले भी समाप्त किया जा सकता है?

- लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत से संकल्प पारित हो जाये क्या संविधान में लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के शपथ ग्रहण का अलग से कोई प्रावधान वर्णित है?

- नहीं

■ लोकसभा के सदस्यों के पारित संकल्प द्वारा भी लोकसभा अध्यक्ष को पदच्युत किया जा सकता है। ऐसा संकल्प कितनों दिनों की पूर्व सूचना पर ही लाया जा सकता है?

- 14 दिन

■ लोकसभा उपाध्यक्ष को हटाने वाले प्रस्ताव की सूचना कितने दिन पूर्व देनी पड़ती है?

- 14 दिन पूर्व

■ जब लोकसभा अध्यक्ष को हटाये जाने की कार्यवाही होती है, तब वह सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकता; लेकिन क्या उसे सदन में बोलने तथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है?

- हाँ

■ लोकसभा उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा लोकसभा अध्यक्ष को देता है। अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा करता है? - लोकसभा उपाध्यक्ष

■ जब लोकसभा अध्यक्ष पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करता है तो उसे किस प्रकार की शक्ति प्राप्त होती है?

- अर्द्ध न्यायिक शक्ति

■ जब लोकसभा का विघटन कर दिया जाता है, तो लोकसभा अध्यक्ष कब तक अपना पद रिक्त नहीं करता? - लोकसभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक

■ लोकसभा उपाध्यक्ष जब सदन की अध्यक्षता नहीं करता है तब उसको एक सामान्य सदस्य की तरह सदन की कार्यवाहियों में भाग लेने और किसी मुद्रे पर मतदान का अधिकार प्राप्त होता है। क्या लोकसभा अध्यक्ष को उक्त अधिकार होता है? - नहीं

■ लोकसभा अध्यक्ष को सदन में साधारणतः मतदान का अधिकार नहीं है, इसके बावजूद वह किस दशा में अपना निर्णयिक मत दे सकता है?

- केवल मत बराबर होने की दशा में

■ क्या कोई सांसद लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में शपथ लेता है?

- नहीं, वह केवल सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है

■ लोकसभा का सत्रावसान एवं विघटन किसके द्वारा किया जाता है? - राष्ट्रपति द्वारा

■ राष्ट्रपति किसकी सलाह पर लोकसभा को भंग करता है? - प्रधानमंत्री की सलाह पर

■ लोकसभा के सदस्यों की निर्यायता से संबंधित प्रश्नों का निर्णय कौन करता है?

- लोकसभा का अध्यक्ष

■ आप चुनाव के बाद गठित लोकसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है?

- प्रोटेम स्पीकर

■ परम्परा के अनुसार, लोकसभा के वरिष्ठतम् सदस्य को प्रोटेम स्पीकर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है?

- राष्ट्रपति द्वारा

■ प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति क्यों की जाती है?

- नवनिर्वाचित सदस्यों को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाने के लिए

■ लोकसभा एवं राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या क्या है?

- कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग

- 60 दिन तक

■ कितने दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहने पर लोकसभा के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है?

■ किन परिस्थितियों में संसद लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है?

- आपातकाल की स्थिति में

## अध्याय 3

राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां

• अनुच्छेद 123: संसद के विश्रांतिकाल में अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति

### राज्यवार लोकसभा और राज्यसभा के सीटों की संख्या

| क्रम राज्य              | लोकसभा     | राज्यसभा   |
|-------------------------|------------|------------|
| 1. आंध्र प्रदेश         | 25         | 11         |
| 2. अरुणाचल प्रदेश       | 2          | 1          |
| 3. असम                  | 14         | 7          |
| 4. बिहार                | 40         | 16         |
| 5. गोवा                 | 2          | 1          |
| 6. गुजरात               | 26         | 11         |
| 7. हरियाणा              | 10         | 5          |
| 8. हिमाचल प्रदेश        | 4          | 3          |
| 9. कर्नाटक              | 28         | 12         |
| 10. केरल                | 20         | 9          |
| 11. मध्य प्रदेश         | 29         | 11         |
| 12. महाराष्ट्र          | 48         | 19         |
| 13. मणिपुर              | 2          | 1          |
| 14. मेघालय              | 2          | 1          |
| 15. मिजोरम              | 1          | 1          |
| 16. नगालैंड             | 1          | 1          |
| 17. ओडिशा               | 21         | 10         |
| 18. पंजाब               | 13         | 7          |
| 19. राजस्थान            | 25         | 10         |
| 20. सिक्किम             | 1          | 1          |
| 21. तमिलनाडु            | 39         | 18         |
| 22. त्रिपुरा            | 2          | 1          |
| 23. उत्तर प्रदेश        | 80         | 31         |
| 24. पश्चिम बंगाल        | 42         | 16         |
| 25. छत्तीसगढ़           | 11         | 5          |
| 26. उत्तराखण्ड          | 5          | 3          |
| 27. झारखण्ड             | 14         | 6          |
| 28. तेलंगाना            | 17         | 7          |
| <b>संघ राज्यक्षेत्र</b> |            |            |
| 1. दिल्ली               | 7          | 3          |
| 2. अंडमान व निकोबार 1   | -          | -          |
| 3. चंडीगढ़              | 1          | -          |
| 4. दादरा व नगर हवेली    | -          | -          |
| तथा दमन व दीव           | 2          | -          |
| 5. लक्ष्मीपुर           | 1          | -          |
| 6. पुडुचेरी             | 1          | 1          |
| 7. जम्मू व कश्मीर       | 5          | 4          |
| 8. लद्दाख               | 1          | -          |
| <b>कुल</b>              | <b>543</b> | <b>233</b> |

- संसद एक बार में लोकसभा के कार्यकाल में कितने समय के लिए वृद्धि कर सकती है? - **एक वर्ष के लिए**
- किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था? - **42वें संविधान संशोधन द्वारा**
- किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल एक-एक करके दो बार बढ़ाया गया था? - **1976 में**
- भारतीय संसद की संप्रभुता किससे प्रतिबंधित है? - **मूल संरचना की न्यायिक समीक्षा से**
- संविधान के अनुच्छेद 107 से 122 तक विधायी प्रक्रियाओं अर्थात् कानून निर्माण की प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है। कानून निर्माण हेतु जो प्रस्ताव पेश किये जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? - **विधेयक (Bill)**
- भारतीय संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस प्रकार के विधेयक के संबंध में बुलाई जा सकती है? - **साधारण विधेयक**
- किन विधेयकों पर दोनों सदनों में गतिरोध होने के बावजूद संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है? - **संविधान संशोधन विधेयक एवं धन विधेयक पर**
- अनुच्छेद 108 के तहत साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? - **राष्ट्रपति**
- संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? - **लोकसभा अध्यक्ष**
- स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में भारतीय संसद की संयुक्त बैठक अब तक तीन बार हुई है। पहली संयुक्त बैठक 6 मई, 1961 को बुलायी गयी थी, जो दो दिन चली थी। इसमें किस विधेयक को पारित किया गया था? - **दहेज निरोधक विधेयक**
- दूसरी संयुक्त बैठक 16 मई, 1978 को हुई थी, जिसमें बैंकिंग सेवा आयोग से संबंधित विधेयक पारित हुआ। तीसरी संयुक्त बैठक 26 मार्च, 2002 को हुई। इस बैठक में किस विधेयक को पारित किया गया?
- **आतंकवाद निरोधक विधेयक (POTA: Prevention of Terrorism Act)**
- भारत में दो अपवाद या दो प्रकार के विधेयक हैं, जिसके लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलायी जा सकती। पहला है संवैधानिक संशोधन विधेयक जिसको अनुच्छेद 368 के तहत दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत की जरूरत पड़ती है। दूसरा विधेयक कौन-सा है? - **धन विधेयक (अनुच्छेद 109 और 110)**
- किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाया सकता है, संसद के दोनों सत्रों का सत्रावसान कर सकता है अथवा लोकसभा का विघटन कर सकता है? - **अनुच्छेद 85**
- राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अनुसार संसद के किसी एक सदन में एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण करने तथा इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा करने का अधिकार होता है? - **अनुच्छेद 86(1)**
- राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकता है? - **अनुच्छेद 87(1)**
- लोकसभा को प्रधानमंत्री की सिफारिश पर कौन भंग कर सकता है? - **राष्ट्रपति**
- संविधान के अनुसार, संसद के दो अधिवेशन एक वर्ष में अवश्य बुलाये जाने चाहिए, परंतु दो अधिवेशनों के बीच की अधिकतम अवधि छह मास निर्धारित है। भारत में सामान्यतः इसके तीन अधिवेशन कौन-कौन से होते हैं?
- **1. बजट अधिवेशन 2. मानसून अधिवेशन तथा 3. शीतकालीन अधिवेशन**
- संसदीय शासन प्रणाली में भारत की देन है? - **शून्यकाल**
- किस विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग-अलग विशेष बहुमत से पारित करना आवश्यक होता है? - **संविधान संशोधन विधेयक को**
- संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु लोकसभा का गठन कब हुआ था? - **1989 में (नौवां लोकसभा)**

## संसदीय विशेषाधिकार

संसद के दोनों सदनों और राज्य के विधानमंडलों के संविधान के अधीन एक जैसे विशेषाधिकार हैं। संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 के खंड (1) एवं (2) इन विषयों से सम्बद्ध हैं। अनुच्छेद 105 में संसद के दोनों सदनों तथा उनके सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों का वर्णन किया गया है। प्रत्येक सदन के विशेषाधिकारों को निम्न प्रकार विभाजित किया जा सकता है-

1. **प्रत्येक सदस्य द्वारा व्यक्तिशः**: उपभोग किये जाने वाले विशेषाधिकार
- **गिरफ्तारी से उन्मुक्ति**: संसद के सत्र या उसकी किसी समिति की बैठक के दौरान तथा उसके 40 दिन पहले व 40 दिन बाद दीवानी मामले में किसी सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, लेकिन आपराधिक मामले में यह लागू नहीं होता है, पर इस गिरफ्तारी की मूल्यना अध्यक्ष या सभापति को देनी पड़ती है।
- **माक्षी के रूप में हाजिरी से मुक्ति**: संसद के सत्र के दौरान सदन की अनुमति के बिना किसी सदस्य को समन भेजकर गवाही के लिए नहीं बुलाया जा सकता।
- **वाक् स्वतंत्रता**: संसद या उसकी किसी समिति में कही गयी किसी बात या प्रकट किये गये किसी मत या विचार के लिए सांसद पर न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।
2. **सदन के सामूहिक विशेषाधिकार**
- **चर्चा और कार्यवाहियां**: प्रकाशित करने और अन्य व्यक्तियों को प्रकाशित करने से रोकने का अधिकार। 1975 की आपात स्थिति के दौरान लोकसभा ने सदन की कार्यवाही को प्रकाशित करने पर रोक लगादी।
- **अन्य व्यक्तियों को अपवर्जित करने का अधिकार**
- **सदन के अंतरिक मामलों को विनियमित करने का और चारदीवारी के भीतर उत्पन्न होने वाले मामलों को निपटाने का अधिकार।**
- **संसदीय कदाचार को प्रकाशित करने का अधिकार।**
- **सदस्यों को बाहरी व्यक्तियों को सदन के विशेषाधिकारों को भंग करने के लिए दंडित करने का अधिकार।**

## भारतीय संसद

यदि कोई व्यक्ति राज्यसभा से मंत्री है तो क्या वह लोकसभा में वक्तव्य दे सकता है? - हाँ  
संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है?

- मंत्री के अतिरिक्त अन्य सभी संसद के सदस्यों को

यदि सभापति का पद रिक्त हो या वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो तो सभापति का कार्य उपसभापति करेगा, यदि उपसभापति का पद भा रिक्त हो तो सभापति का कार्य कौन करेगा?

- राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति

किस अनुच्छेद के तहत यदि राष्ट्रपति की दृष्टि में आंग्ल भारतीय समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिला है, तो राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के दो सदस्यों को मनोनीत कर सकता है?

- अनुच्छेद 331 के तहत

वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित है?

- क्रमशः 84 एवं 44

किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गयी थी?

- 61वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1989 द्वारा

किस विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जाता है? - धन विधेयक को लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है?

- 14 दिन

धन विधेयक की शुरुआत लोकसभा में ही हो सकती है। इसके लिए किसकी पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है?

- राष्ट्रपति की

कौन-सा विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्या उसका निर्णय अंतिम माना जाता है?

- हाँ

धन विधेयक का तात्पर्य अनुच्छेद 110 से संबंधित विषयों से है। धन विधेयक को प्रमाणित करने का अधिकार किस व्यक्ति को है जिसका निर्णय अंतिम होता है?

- लोकसभा का अध्यक्ष

धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा द्वारा पारित करने के बाद उसे राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा 14 दिन के अंदर अपनी सिफारिशों सहित लोकसभा को अवगत नहीं करती है, तो धन विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

- धन विधेयक पास माना जायेगा

धन विधेयक तथा वित्त विधेयक में दो बातें समान हैं, पहला दोनों विधेयक लोकसभा में पेश किये जाते हैं और दूसरा इन दोनों विधेयकों को लोकसभा में पेश करने से पहले किसकी अनुमति आवश्यक होती है?

- राष्ट्रपति की

राज्यसभा धन विधेयक को केवल 14 दिनों तक अपने पास रोक सकती है, परंतु वित्त विधेयक को वह कितने दिनों तक रोक सकती है? - 180 दिनों (6 माह तक)

- गणेश वासुदेव मावलंकर

लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे?

- पी.ए. संगमा

अनुसूचित जाति से संबंधित प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे? - जी.एम.सी. बालयोगी

- मीरा कुमार

लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थीं?

- नीलम संजीव रेडी

कौन लोकसभा अध्यक्ष ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? - नीलम संजीव रेडी

लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? - लोकसभा का अध्यक्ष

किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा द्वारा संसद को राष्ट्रीय हित में, राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत किया जा सकता है? - अनुच्छेद 249 के तहत

किस अनुच्छेद के तहत यदि राष्ट्रीय हित में या वैसे अनिवार्य समझकर राज्यसभा

उपस्थित व बोट देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके अखिल भारतीय सेवाएं गठित करती

- अनुच्छेद 312

वर्ष 1963 में अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा को प्रदत्त उक्त शक्ति का प्रयोग कर किस सेवा को गठित किया गया था?

- भारतीय वन सेवा (1964 में)

### 3. अन्य विशेषाधिकार

- लोकसभा के अध्यक्ष व राज्यसभा के सभापति को अधिकार है कि वे किसी व्यक्ति को दीर्घ से हटा सकते हैं।
- उन्हें यह अधिकार है कि वे किसी व्यक्ति के सदन में प्रवेश पर रोक लगा सकते हैं।
- प्रत्येक सदन अपनी कार्यवाही को नियंत्रित कर सकता है।
- सदन के अंदर उत्पन्न होने वाले विवादों का सदन स्वयं निपटारा कर सकता है।
- यदि कोई दर्शक या बाहरी व्यक्ति सदन के विशेषाधिकारों को भंग करता है, तो सदन उसे दंडित कर सकता है। यह दंड भर्त्सना, बाक्ताड़न या कारावास के रूप में हो सकता है। ब्लिंडज के सम्पादक आरके. कर्जिया को एक सदस्य की प्रतिकूल लेख प्रकाशित करने पर लोकसभा में बुलाकर डांटा गया था। 1990 में पूर्व मंत्री के के. तिवारी को भी राज्यसभा में इसी प्रकार दंडित किया गया था।

### प्रश्न काल व शून्यकाल

लोकसभा का पहला घंटा प्रश्न काल (*Question Hour*) से संबंधित होता है। इसमें सरकारी मामले से संबंधित प्रश्न ही अधिक होते हैं। मर्त्रियों से पूरक एवं अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। प्रश्न काल के तुरंत बाद का घंटा शून्य काल (*Zero Hour*) कहलाता है। यह दोपहर 12 बजे प्रारंभ होता है। संसद के सदस्य शून्य काल में सार्वजनिक हित से संबंधित मामलों को उठाते हैं। पहले यह 30 मिनट का होता था, परंतु नौवें लोकसभाध्यक्ष रवि राय के कार्यकाल में इसे बढ़ाकर एक घंटे कर दिया गया। प्रक्रिया के नियमों में शून्य काल का उल्लेख नहीं है। यह संसदीय प्रक्रियाओं के क्षेत्र में भारत का आविष्कार है। यह 1962 में अस्तित्व में आया। राज्यसभा में दिन की शुरुआत शून्य काल से होती है, जबकि लोकसभा की शुरुआत प्रश्न काल से होती है।

- सदन की कार्यवाही को कुछ घटे या दिन या सप्ताह के लिए स्थगित करने को क्या कहा जाता है? - **स्थगन**
- सत्रावसान से संसद में लम्बित विलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, केवल मूचनाएं, प्रस्ताव और संकल्प समाप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार स्थगन का, भी किसी कार्यवाही पर प्रभाव नहीं पड़ता परंतु लोकसभा के विघटन से उसमें लम्बित विधेयक पर क्या प्रभाव पड़ता है?
  - **लम्बित सभी विधेयक विधेयक, मूचनाएं एवं प्रस्ताव समाप्त हो जाते हैं।**
- वे विशिष्ट अधिकार, जो संसद के दोनों सदनों को, उनके सदस्यों को और समितियों को प्राप्त हैं, जिनके बिना वे अपने कृत्यों का यथोचित और निर्वाध निर्वहन नहीं कर सकते, को क्या कहा जाता है? - **संसदीय विशेषाधिकार**
- संविधान के अनुच्छेद 105 में संसद के दोनों सदनों तथा उनके सदस्यों के विशेषाधिकारों का वर्णन किया गया है, परंतु संसद का कोई सदस्य सदन की अनुमति के बिना कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है?
  - **लगातार 60 दिनों तक**
- सदन के अधिवेशन के दौरान और उसके प्रारम्भ होने से कितने दिन पूर्व और समाप्ति है?
  - **दोनों समितियों में 40- 40 दिन**
- संसद के सदन प्रकाशन संबंधी कानून बनाकर अपनी कार्यवाही के प्रकाशन पर रोक लगा सकता है या उसे अधिनियमित कर सकता है। सदन अपने इस अधिकार का प्रयोग कब किया था?
- संसदीय विशेषाधिकार के तहत किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सदन की पूर्व अनुमति के बिना संसद की कार्यवाही का प्रेस में प्रकाशन को मना किया गया?
  - **1975 की आपानकाल के दौरान**
- किसकी अनुमति के बिना संसद के परिसर में किसी प्रकार की गिरफ्तारी और कानूनी आदेशिका की तामील नहीं की जा सकती है? - **अध्यक्ष की अनुमति के बिना**
- किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा अपने कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह संकल्प पारित कर दे कि राष्ट्रीय हित में संसद नयी अखिल भारतीय सेवा की स्थापना कर सकती है?
  - **44वें संविधान संशोधन अधिनियम (1978) द्वारा**
- एक वर्ष में कितनी बार संसद का अधिवेशन बुलाया जाना आवश्यक है? - **दो बार**
- संसद के सत्र या उसकी किसी समिति की बैठक के दौरान तथा उसके 40 दिन पहले गिरफ्तारी की सूचना किसको देनी पड़ती है? - **सदन के अध्यक्ष एवं सभापति को**
- जब तक कि दोनों सदनों की अलग-अलग कुल संख्या की 1/10 भाग के बराबर न हो गयी हो?
  - **अनुच्छेद 312 के अंतर्गत**
- किस संवैधानिक संशोधन से यह प्रावधान कर दिया गया है कि यदि कोई संसद सदस्य अपने पद से इस्तीफा देता है तो उसकी सदस्यता तब तक समाप्त नहीं मानी जायेगी जब तक अध्यक्ष या सभापति ने यह जांच न कर ली हो कि इस्तीफा उसी व्यक्ति का है, जिसने की इस्तीफा दिया था?
  - **अनुच्छेद 100 के तहत**
- जब लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद हटाने से संबंधित कोई प्रस्ताव सदन में है, किंतु मत बराबर की स्थिति में मत नहीं देगा, लेकिन प्रथमतः मत दे सकेगा या नहीं?
  - **दे सकेगा**

## अविश्वास प्रस्ताव

संसदीय शासन में मत्रिपरिषद वर्षों तक पदार्थीन रहती है, जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन हो। यदि लोकसभा मत्रिपरिषद या कार्यपालिका गे अपना तो वह उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव (No-Confidence Motion) ला सकती है। इस प्रस्ताव पर लोकसभा के 1/10 मत्रियों का अनुमतर्थन चाहिए। इसे लोकसभा में प्रस्तुत किये जाने के बाद यदि लोकसभा का बहुमत इसे स्वीकार करता है, तो कार्यपालिका बर्खास्त हो जाती है। यान्त्र में, यह कार्यपालिका के नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसका उल्लेख लोकसभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 198 में किया गया है। इसका प्रयोग सर्वप्रथम 1962 में किया गया था।

## स्थगन प्रस्ताव

'स्थगन प्रस्ताव' (Adjournment Motion) सार्वजनिक महत्व के विषयों से सम्बद्ध होता है। यह प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में लाया जा सकता है। यदि स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है, तो उसके नियम को 10 बजे से पहले अध्यक्ष को मूचित करना पड़ता है। यदि अध्यक्ष सहमत है, तो उसकी स्वीकृति से स्थगन प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसे प्रस्तुत करने से पहले अध्यक्ष उसे सदन की अनुमति लेने को भी कह सकता है। यदि संसद के दोनों सदनों का सत्र चल रहा हो एवं कोई सार्वजनिक महत्व की घटना हो जाये, तो इस प्रस्ताव द्वारा सदन के सदस्य लोकसभा के नियमित काम को रोककर उस लोक महत्व के प्रस्ताव पर चर्चा करते हैं।

## ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

'ध्यानाकर्षण प्रस्ताव' (Calling Attention Notice) द्वारा सदन के सदस्य सरकार का ध्यान लोक महत्व के उस विषय की ओर दिलाते हैं, जो बहुत जहरी होता है। इस प्रस्ताव की मूचना भी उस तिथि को 10 बजे दिन से पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष को देनी होती है। अध्यक्ष की अनुमति के बाद ही प्रस्ताव पेश किया जाता है। इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का आधार समाचार पत्रों में छपी घटनाएं आदि होती

## भारतीय संसद

अनुच्छेद 120 के अनुसार, संसद की कार्यवाही अंग्रेजी या हिंदी में होगी, लेकिन संसद के दोनों सदनों में कोई सदस्य सदन में अपनी मातृभाषा में बोल सकता है। सदन में मातृभाषा में बोलने का अधिकार कौन दे सकता है? - **लोकसभा अध्यक्ष एवं राज्यसभा सभापति** किन अनुच्छेदों के तहत संसद के सदस्यों को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के कर्तव्यों या आचरण के बारे में चर्चा का प्रतिषेध किया गया है, सिवाय जब किसी न्यायाधीश के ऊपर महाभियोग की कार्यवाही चल रही हो तब सदस्य चर्चा कर सकते हैं?

- **अनुच्छेद 121 एवं 211**

किस अनुच्छेद के अनुसार, किसी भी न्यायालय को संसद की कार्यवाहियों की जांच से प्रतिषेध किया गया है?

- **अनुच्छेद 122**

सामान्य आपात स्थिति का अनुमोदन संसद 30 दिन के अंदर करती है, जबकि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एवं वित्तीय आपातकाल की स्थिति का अनुमोदन संसद कितने दिनों में करती है?

- **60 दिन या 2 माह के अंदर**

अनुच्छेद 110 से संबंधित विषयों के अतिरिक्त अन्य विषयों से संबंधित विधेयक को साधारण विधेयक कहते हैं। साधारण विधेयक किसी भी सदन में पेश किये जा सकते हैं। इन विधेयकों को पारित होने के लिए कितने चरणों से होकर गुजरना पड़ता है?

- **तीन चरणों से**

विधि-निर्माण से संबंधित विधेयक को दोनों सदनों में तीन-तीन वाचनों से गुजरना पड़ता है। प्रथम वाचन में सिर्फ विधेयक पर थोड़ी-बहुत चर्चा होती है। इसकी नीति एवं सिद्धांतों पर किस वाचन में चर्चा होती है?

- **द्वितीय वाचन में**

किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है कि संसद के दो सत्रों के बीच छह माह का अंतर नहीं होगा?

- **अनुच्छेद 85(1) में**

वर्ष 1921 में किस समिति ने आम बजट से रेलवे बजट को अलग करने की सिफारिश की?

- **विलियम एक्वर्थ कमेटी**

भारत में किस वर्ष से रेल बजट अलग से पेश किया जाने लगा? - **वर्ष 1924 से**

किस वित्तीय वर्ष के आम बजट में रेल बजट का फिर से विलय कर दिया गया?

- **वर्ष 2017-18**

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 एवं 202 के अनुसार क्रमशः राष्ट्रपति एवं राज्यपाल संसद तथा राज्य विधानमंडलों में प्रतिवर्ष बजट प्रस्तुत करवाते हैं। बजट को संविधान में किस नाम से जाना जाता है?

- **वार्षिक वित्तीय विवरण**

संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण अथवा बजट को पारित होने का सही क्रम क्या है? - **बजट का प्रस्तुतिकरण > आम बहस > विभागीय समितियों द्वारा जांच > अनुदान मांग पर मतदान > विनियोग विधेयक का पारित होना > विधेयक का पारित होना**

लोकसभा किसी अनुदान की मांग को स्वीकार कर सकती है, कम कर सकती है या उसे अस्वीकार कर सकती है। क्या वह किसी अनुदान की मांग को बढ़ा सकती है? - **नहीं**

राज्यसभा 'वार्षिक वित्तीय विवरण' पर चर्चा तो करती है, परंतु वह अनुदान की मांगों पर मतदान कर सकती है या नहीं?

किसी वित्तीय वर्ष के भाग के लिए प्राकलित व्यय के संबंध में ऐसा अनुदान, जो बजट प्रक्रिया के पूरे होने तक सरकारी कार्यों के संचालन के लिए दिया जाता है, क्या कहलाता है?

- **लेखानुदान**

जब किसी सेवा या मद के लिए आकस्मिक रूप से धन की अत्यधिक एवं तुरंत आवश्यकता होती है, तो किस प्रकार की अनुदान मांगें रखे जाती हैं? - **प्रत्यानुदान**

किस अनुच्छेद के अनुसार भारत की संचित निधि पर भारित व्यय से संबंधित प्राकलन संसद के मतदान के लिए व्यय के मद पर विचार-विर्माश करती है? - **अनुच्छेद 113**

अनुच्छेद 266 के अनुसार, संचित निधि से कोई भी व्यय विनियोग विधेयक के द्वारा ही निकाला जायेगा अन्यथा नहीं। विनियोग विधेयक को सदन में पेश करने से पहले

- **राष्ट्रपति की**

किसकी पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है?

हैं। इसका प्रयोग भारत में 1954 से हो रहा है। प्रक्रिया व कार्य संचालन नियम 197 में इसकी चर्चा है।

## तारांकित व अतारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न वह प्रश्न होता है, जिसका उत्तर मर्मियों को मौखिक रूप से देना पड़ता है। चूंकि इसमें तारांक लगा होता है, इसलिए इसे तारांकित प्रश्न कहते हैं। इसका उल्लेख कार्य संचालन नियम 36 में किया गया है। इसमें मर्मियों से पूरक एवं अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। दूसरी तरफ अतारांकित प्रश्न का उत्तर लिखित रूप में देना पड़ता है, किंतु इसमें अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते। इसका उल्लेख लोक कार्य संचालन नियम 39 में है। इस प्रकार के प्रश्नों में तारांक नहीं लगा होता है।

## व्यवस्था का प्रश्न

व्यवस्था का प्रश्न (Point of Order) सदन में तभी उठता है, जब सदन की मान्य परम्परा एवं नियमों का उल्लंघन किया जा रहा हो। इसमें यह बताना पड़ता है कि किस नियम का उल्लंघन हो रहा है या किस प्रक्रिया की अवहेलना हो रही है। यदि सभापति या अध्यक्ष सहमति देता है, तो व्यवस्था का प्रश्न दोनों सदनों में उठाया जा सकता है।

## विनियोग विधेयक

विनियोग विधेयक (Appropriation Bill) एक प्रकार से धन विधेयक है। जब संसद में प्राकलनों पर विचार हो चुका होता है, तो ये सभी प्राकलन एक विनियोग के रूप में अनुच्छेद 114 के तहत बदल जाते हैं। विनियोग विधेयक यह बताता है कि किस मदों में कितने-कितने आय-व्यय होंगे। इसी के आधार पर विनियोग के माध्यम से भारत की संचित निधि से धन लिया जाता है, इसीलिए इसे 'विनियोग विधेयक' कहते हैं।

## लेखानुदान

बजट पर संसद में चर्चा एवं मतदान होने से पहले नये वित्त वर्ष का प्रारंभ हो जाने की स्थिति में वित्तीय संसाधनों के लिए संचित निधि से धन निकालने के लिए 'लेखानुदान' (Vote on Accounts) पारित कराया जाता है। यह सरकार के मात्र व्यय पक्ष से संबद्ध होता है। इसको स्थायी और

## किंदण NCERT भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान सार संग्रह (By : Khan Sir, Patna)

- जब सभी अनुदानों को सदन की स्वीकृति मिल जाती है तो अनुदानों और संचित निधि के विनियोग करने से संबंधित विधेयक को क्या कहा जाता है? - **विनियोग विधेयक** विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति सरकार को किस निधि से अग्रिम धनराशि दे सकता है?  
- **आकस्मिक निधि से**
- भारत के संसदीय व्यवहार में 'शून्य काल' की शुरुआत कब हुई थी? - **वर्ष 1962** में किस संविधान संशोधन के अनुसार, दल परिवर्तन करने वाला व्यक्ति मंत्री नहीं हो सकता है। वह इसके अलावा संवेतन राजनीतिक पद धारण करने के लिए भी निरर्हित हो जायेगा। यह निरर्हित तब तक बनी रहेगी जब तक सदस्य के रूप में उसकी पदावधि समाप्त नहीं हो जाती या जब तक वह किसी सदन के लिए निर्वाचन में भाग नहीं लेता या किसी सदन के लिए निर्वाचित घोषित नहीं किया जाता? - **91वां संविधान संशोधन** किस अधिनियम में कहा गया है कि यदि दल-बदल का प्रश्न उठता है तो इसमें सदन के अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होगा एवं किसी न्यायालय को उसमें हस्तक्षेप का अधिकार नहीं होगा?  
- **दल-बदल अधिनियम, 1985**
- सामान्य स्थिति में किसी भी सदन के सदस्यों की निरहता संबंधी मामलों में राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होता है, परंतु दसवीं अनुसूची (दल-बदल) की निरहता पर अंतिम निर्णय किसका होता है? - **राज्यसभा में सभापति व लोकसभा में अध्यक्ष** भारतीय संसद अपना अधिकांश कार्य समितियों के माध्यम से करती है। भारत में समिति प्रणाली का विकास प्राचीन काल से ही था, लेकिन आधुनिक समय में समिति प्रणाली का विकास किस अधिनियम से हुआ? - **भारत शासन अधिनियम 1919 से** लोकसभा की सभी समितियों (संसदीय) के सभापति की नियुक्ति कौन करता है?  
- **लोकसभा अध्यक्ष**
- लोकसभा का उपाध्यक्ष जब किसी संसदीय समिति का सदस्य बनता है, तो वह स्वाभाविक रूप से उसको उस समिति में कौन-सा पद दिया जाता है? - **अध्यक्ष** संसद के प्रति कार्यपालिका की जबाबदेही को सुनिश्चित करने, विशेषकर वित्तीय उत्तरदायित्व का वहन करने के उद्देश्य से लोकसभा नियमावली समिति की सिफारिश पर किस वर्ष विभागीय समितियों का गठन किया गया, जिनकी संख्या वर्तमान में 24 हो गयी है?  
- **वर्ष 1993 में** किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए नियुक्त समितियां जब अपना काम समाप्त कर लेती हैं तथा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देती हैं, तब उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। विधेयकों से संबंधित प्रवर समितियां और संयुक्त संसदीय समितियां इसी प्रकार की समितियां हैं। इन समितियों को क्या कहा जाता है? - **तदर्थ समितियां**
- किस समिति में सबसे अधिक (तीस सदस्य) होते हैं, जिनका चुनाव केवल लोकसभा के सदस्यों में से प्रतिवर्ष आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से होता है? - **प्राक्कलन समिति**
- बजट में सम्मिलित अनुमानों की जांच करने एवं मितव्ययिता का सुझाव देने के लिए प्राक्कलन समिति का पहली बार गठन 1950 में किया गया। इसका अध्यक्ष किस दल का होता है?  
- **सत्तारूढ़ दल** लोक लेखा समिति का गठन भारत सरकार अधिनियम, 1919 के तहत 1921 में किया गया। इसकी सदस्य संख्या कितनी होती है?  
- **22 सदस्य ( 15 लोकसभा व 7 राज्यसभा से )**
- केंद्र सरकार के विनियोग खातों एवं वित्तीय खातों की जांच करने तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की वार्षिक रिपोर्ट का परीक्षण करने के लिए गठित लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किस वर्ष से विषपक्षी दल से ही चुना जाता है? - **वर्ष 1967 से**
- आम चुनाव के उपरांत लोकसभा के गठन के बाद किस 15 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है, जिसका अध्यक्ष स्वयं लोकसभाध्यक्ष होता है? - **कार्यमंत्रणा समिति**
- भारत सरकार ने सरकारी उपक्रमों पर समुचित नियंत्रण रखने के लिए या जांच करने के लिए एक अलग संसदीय समिति के गठन का फैसला 24 नवंबर, 1961 को किया था, परंतु इसका गठन कब किया गया?  
- **मई 1964 में**

कार्यवाहक दोनों तरह सरकारें प्रस्तुत कर सकती हैं। इसके माध्यम से सरकार पूरे बजटीय वर्ष के लिए एक निश्चित राशि निश्चित अवधि के लिए लोक लेखा से निकाल लेती है। इसे लोकसभा वाधित नहीं करती और सहजता से वह इस राशि को स्वीकार कर लेती है। इस प्रावधान का उल्लेख अनुच्छेद 116 में किया गया है।

### संचित निधि

अनुच्छेद 266 के अनुसार, भारत के लिए एक संचित निधि (*Consolidated Fund*) होगी। इस निधि में विभिन्न उधार, करों एवं राजस्वों से प्राप्त आय, अन्य साधनों से लिये गये अग्रिम धन एवं विभिन्न प्राप्तियां आदि शामिल होती हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक तथा न्यायाधीशों (सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय) के वेतन एवं भत्ते भारत की संचित निधि पर ही भारित होते हैं। राज्यों के संबंध में राज्यों की संचित निधि में करों एवं राजस्वों से प्राप्त आय, अन्य शुद्ध आगम, अन्य साधनों से लिया गया अग्रिम धन, विभिन्न उधार एवं प्राप्त अन्य राशियां आदि आती हैं। अनुच्छेद 266(3) के अनुसार, भारत की या राज्य की संचित निधि से धन विधिक प्रक्रिया के द्वारा ही निकाला जा सकता है, अन्यथा नहीं।

### आकस्मिक निधि

अनुच्छेद 267(1) के अनुसार, संसद विधि द्वारा अग्रदाय के रूप में भारत के लिए एक 'आकस्मिक निधि' (*Contingency Fund*) व्यवस्था करेगी, जिसमें विधि द्वारा प्रख्यापित राशियां रखी जायेंगी। इस पर राष्ट्रपति का अधिकार होगा। संसद विधि द्वारा सरकार को इसमें से अग्रिम धन विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दे सकती है। अनुच्छेद 267(2) में कहा गया है कि राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अग्रदाय के रूप में राज्य के लिए एक 'आकस्मिक निधि' की स्थापना करेगा, जिसमें राज्य विधानमंडल द्वारा अवधारित राशियां जमा की जायेंगी। इस पर राज्यपाल का नियंत्रण होगा। राज्य विधानमंडल किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसमें से अग्रिम धन दे सकता है।

कृष्ण मेनन समिति के सुझाव पर 1964 में गठित सरकारी उपक्रम संबंधी समिति में कुल सदस्यों की संख्या 22 होती है, जिनमें से 15 लोकसभा एवं 7 राज्यसभा से होते हैं। इसका अध्यक्ष किस सदन से होता है?

विधेयकों की समीक्षा करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में अलग-अलग प्रवर समितियों का गठन किया जाता है, जिनकी सदस्य संख्या 30-30 होती है। कई मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त प्रवर समिति का भी गठन किया जाता है। इस समिति की कुल सदस्य संख्या कितनी होती है? - 45 (30 लोकसभा + 15 राज्यसभा)

भारतीय संसद में कोई विधेयक प्रवर समिति को किस अवस्था में भेजा जा सकता है?

- अध्यक्ष के विवेक से किसी भी अवस्था में

संसद के किसी सदन या अध्यक्ष द्वारा विशेषाधिकार उल्लंघन से संबंधित प्रेपित मामलों का परीक्षण कौन-सी समिति करती है, जिसके सदस्यों की कुल संख्या 15 होती है?

- विशेषाधिकार समिति

कौन-सा प्रस्ताव केवल लोकसभा में सदन के विपक्षी दल द्वारा लाया जा सकता है। यह प्रस्ताव किसी मंत्री के विरुद्ध खिलाफ नीतियों की असहमतियों के संदर्भ में लाया जा सकता है, लेकिन ऐसे प्रस्ताव को लाने के लिए कारण को स्पष्ट करना आवश्यक होता है?

- निंदा प्रस्ताव

लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य है विनियोग लेखों की जांच करना, जिसमें भारत सरकार के खर्च के लिए संसद द्वारा अनुदत्त राशियों का विनियोग दिखाया जाता है। इसके साथ ही भारत सरकार के वार्षिक वित्तीय लेखे और सभा के सामने रखे गये ऐसे अन्य लेखों की परीक्षा करना भी समिति का कार्य है। यह समिति किसके पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करती है? - नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के

### नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (Comptroller & Auditor General of India) का उल्लेख सर्वप्रथम कहां मिलता है? - भारत सरकार अधिनियम, 1919 में

भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है? - अनुच्छेद 148 से 151 तक

भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सार्वजनिक धन का संरक्षक बनाया गया है एवं सम्पूर्ण वित्तीय प्रशासन को उसके अधीन कर दिया गया है। वह स्वतंत्र होकर अपना कार्य कर सके, इसके लिए उसे किसके नियंत्रण से मुक्त रखा गया है?

- कार्यपालिका से

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? - राष्ट्रपति द्वारा

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को किस आधार पर संसद के दोनों सदनों के समावेदन पर हटाया जा सकता है? - साबित कदाचार एवं असमर्थता पर

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) का वेतन एवं उसकी सेवा शर्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? - संसद के द्वारा

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। वह कितने वर्ष के लिए पदग्रहण करता है? - 6 वर्ष के लिए

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पदनाम से यह आभास होता है कि यह नियंत्रण तथा लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता होगा, लेकिन स्वतंत्रता से आज तक कैग का कार्य केवल रह गया है? - लेखा परीक्षण तक सीमित

क्या भारत के संचित निधि से कोई धन व्यय करने से पहले कैग की अनुमति ली जाती है? - नहीं

कैग को पद से हटाने के बही आधार हैं जो अन्य दो संवैधानिक पदों के हैं, वे संवैधानिक पद हैं? - सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं मुख्य निर्वाचन आयुक्त

### विभागीय समिति

1993 में पहली बार विभागीय समितियों का गठन किया गया। अभी विभागीय समितियों की संख्या 24 हो गयी है (16 लोकसभा एवं 8 राज्यसभा से)। प्रत्येक विभागीय समिति में 45 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा से 30 तथा राज्यसभा से 15 सदस्य शामिल होते हैं। कोई मंत्री समिति का सदस्य नहीं बनाया जा सकता है। इन समितियों का प्रमुख कार्य विभिन्न मंत्रालयों के अनुदान संबंधी भागों की जांच करना है। लेकिन ये समितियां संबंधित मंत्रालय या विभाग के दैनिक कामकाज के मामलों पर विचार नहीं करती हैं। ये समितियां किसी अन्य संसदीय समिति के सांगे गये विषय पर विचार नहीं करती हैं।

### गिलोटिन

'गिलोटिन' (Guillotine) एक फ्रांसीसी हथियार है, जिसका प्रयोग सिर काटने में किया जाता था। आजकल इस शब्द का प्रयोग एक संसदीय प्रक्रिया के रूप में होने लगा है। सत्र के दौरान जब किसी निर्धारित विषय की समाप्ति के साथ ही समस्त वाद-विवाद की प्रक्रिया अचानक समाप्त कर दी जाती है, तो इसे 'गिलोटिन' कहते हैं। कई बार सत्र के अंतिम दिन जिन मांगों पर चर्चा न हुई हो, उन्हें भी मतदान के लिए रख दिया जाता है और बिना चर्चा के पारित कर दिया जाता है। इस प्रकार संसद सदस्यों की मुद्दों पर बहस करने की इच्छा का दमन कर दिया जाता है। इसी कारण इस प्रक्रिया को 'गिलोटिन' कहा जाता है।

### भारत के कैग और उनका कार्यकाल

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| 1. वी. नरहरि राव     | 1948 - 1954  |
| 2. ए.के. चंदा        | 1954 - 1960  |
| 3. ए.के. रॉय         | 1960 - 1966  |
| 4. एस. रंगनाथन       | 1966 - 1972  |
| 5. ए. बक्शी          | 1972 - 1978  |
| 6. ज्ञान प्रकाश      | 1978 - 1984  |
| 7. टी.एन. चतुर्वेदी  | 1984 - 1990  |
| 8. सी.जी. सामेया     | 1990 - 1996  |
| 9. वी.के. शुग्लू     | 1996 - 2002  |
| 10. वी.एन. कौल       | 2002 - 2008  |
| 11. विनोद राय        | 2008 - 2013  |
| 12. शशि कांत शर्मा   | 2013 - 2017  |
| 13. राजीव महर्षि     | 2017 - 2020  |
| 14. गिरीशचंद्र मुर्म | 2020 - अब तक |

## उच्चतम न्यायालय

- भारत में अमेरिकी न्याय व्यवस्था को तरह केंद्र और राज्यों में अलग-अलग न्यायालय नहीं हैं। भारत में एकीकृत न्यायपालिका की स्थापना की गयी है। किस अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार फेडरल कोर्ट की स्थापना की गयी थी?
 

- भारत सरकार अधिनियम, 1935
- फेडरल कोर्ट को नये संविधान में सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय के नाम से जाना गया। इस न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया? - 26 जनवरी, 1950 को
- भारतीय संविधान के भाग-5 में किन अनुच्छेदों में उच्चतम न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र, शक्तियाँ, प्रक्रियाओं आदि का उल्लेख किया गया है?
 

- अनुच्छेद 124-147 तक
- संविधान के प्रारम्भ में उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश होते थे, परंतु 1956 में अन्य न्यायाधीशों की संख्या 7 से बढ़कर 10 कर दी गयी। इसी प्रकार 1960 में 13, 1977 में 17, 1986 में 25 कर दी गयी, परंतु वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? - एक मुख्य न्यायाधीश एवं 33 अन्य न्यायाधीश
- उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या मुख्य न्यायमूर्ति के अलावा 30 किस वर्ष की गयी?
 

- वर्ष 2009 में
- संविधान के अनुसार भारतीय न्याय व्यवस्था के शीर्ष पर भारत का उच्चतम न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय के नीचे विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय के नीचे अधीनस्थ या जिला न्यायालय होते हैं। उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गयी है? - अनुच्छेद 124 के अंतर्गत
- मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? - राष्ट्रपति
- उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से पूर्व कम से कम कितने वरिष्ठ न्यायाधीशों से परामर्श करना चाहिए? - चार वरिष्ठ न्यायाधीशों से
- संविधान के अनुच्छेद 124(2) के मुताबिक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद पर बने रहने की अधिकतम आयु कितनी है?
 

- 65 वर्ष
- उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय सामान्यतः वरिष्ठता के सिद्धांत का अनुसरण किया जाता है, परंतु पहली बार इसका उल्लंघन कब किया गया?
 

- 1973 में इंदिरा गांधी द्वारा
- उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस अनुसूची में निर्धारित प्रपत्र के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण करते हैं? - तीसरी अनुसूची में निर्धारित प्रपत्र के अनुसार
- क्या सुप्रीम कोर्ट का प्रत्येक न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने पर भारत राज्य क्षेत्र में स्थित किसी भी न्यायालय में एवं किसी भी अधिकारी के अधीन वकालत कर सकता है? - नहीं
- अनुच्छेद 124(3) के अनुसार, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए निम्न योग्यताओं में जैसे वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 5 वर्ष तक किसी एक, दो या अधिक उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश रह चुका हो या किसी एक, दो या अधिक उच्च न्यायालयों में 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। इन योग्यताओं के अतिरिक्त एक योग्यता और भी है वह है? - राष्ट्रपति की दृष्टि में पारंगत विधिवेत्ता हो
- उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?
 

- कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं

## भाग-5, अध्याय 4

संघ की न्यायपालिका  
( 124-147 )

- अनुच्छेद 124: उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन
- अनुच्छेद 125: न्यायाधीशों के वेतन आदि
- अनुच्छेद 126: कायंकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति
- अनुच्छेद 127: तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति
- अनुच्छेद 128: उच्चतम न्यायालय के वैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति
- अनुच्छेद 129: उच्चतम न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होना
- अनुच्छेद 130: उच्चतम न्यायालय का स्थान
- अनुच्छेद 131: उच्चतम न्यायालय के आरम्भिक अधिकारिता
- अनुच्छेद 132: कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्च न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता
- अनुच्छेद 133: उच्च न्यायालयों से संबंधित अपीलों उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता
- अनुच्छेद 134: दाँड़िक विषय में उच्चतम न्यायालय की अपील अधिकारिता
- अनुच्छेद 134-क: उच्चतम न्यायालय में अपीली के लिए प्रमाण पत्र
- अनुच्छेद 135: विद्यमान विधि के अन्तर्गत फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय प्रयोक्तव्य होना
- अनुच्छेद 136: अपील के लिए उच्च न्यायालय की विशेष इजाजत

## भारतीय न्यायपालिका

- संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायाधीशों को हटाये जाने की प्रक्रिया संक्षेप में बतायी गयी है? - **अनुच्छेद 124(4)**
- उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को किस आधार पर महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है? - **साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर**
- महाभियोग प्रक्रिया के तहत लोकसभा या राज्यसभा के कितने सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति को संबोधित एक प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति को दिया जाता है? - **लोकसभा के कम से कम 100 या राज्यसभा के कम से कम 50 सदस्य**
- महाभियोग की प्रक्रिया तब तक शुरू नहीं की जाती, जब तक उक्त प्रस्ताव की एक जांच समिति यह जांच नहीं कर लेती कि जिस न्यायाधीश को हटाने के लिए जो कारण बताये गये हैं वे सही हैं। इस जांच समिति में कौन-कौन सदस्य के रूप में होते हैं? - **3 सदस्य, दो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश तथा एक प्रथ्यात विधिवेत्ता**
- जांच समिति द्वारा प्रस्ताव को सही ठहराये जाने के बाद संबोधित सदन के कितने सदस्यों द्वारा पारित होने के बाद वह समावेदन राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति द्वारा उसे स्वीकृत कर लेने के उपरांत न्यायाधीश को हटा दिया जाता है? - **संबोधित सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा**
- भारत के संवैधानिक इतिहास में सिर्फ एक बार (1991-93) उच्चतम न्यायालय के किस पूर्व न्यायाधीश पर महाभियोग लगाया गया था, जो पास नहीं हो पाया था? - **श्री आर. रामास्वामी**
- किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों का रक्षक है एवं उसे ऐसी शक्ति दी गयी है कि वह आदेश या लेख जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेषण लेख मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए जारी कर सकता है। - **अनुच्छेद 32 और 139**
- क्या न्यायाधीशों के वेतन एवं सेवा की अन्य स्थितियों को उनके कार्यकाल के दौरान कम किया जा सकता है? - **नहीं**
- किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह न्यायाधीशों के वेतन को कम करे? - **केवल वित्तीय संकट की घोषणा करने पर**
- उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन व भत्तों का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? - **अनुच्छेद 125**
- न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते किस निधि में से दिये जाते हैं? - **भारत की संचित निधि**
- जब मुख्य न्यायाधीश का स्थान खाली हो या वह अनुपस्थित हो या किसी अन्य कारण से अपना कार्य न कर सके, तो उसके स्थान पर उसके कार्यों को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 126 के तहत किसकी नियुक्ति की जाती है? - **कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश**
- यदि स्थायी न्यायाधीशों में गणपूर्ति का अभाव हो तो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से और संबोधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सलाह के बाद किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अस्थायी अवधि के लिए उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है? - **अनुच्छेद 127**
- किसी भी समय भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से उच्चतम न्यायालय में किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्ति कर सकता है। इनकी नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? - **अनुच्छेद 128 के तहत**
- संविधान के अनुच्छेद 129 द्वारा उच्चतम न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय माना गया है। इसका तात्पर्य किन बातों से है? - **इसकी समस्त कार्यवाही तथा निर्णय को प्रमाण के रूप में रखना एवं अपनी अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार रखना**

- **अनुच्छेद 137:** निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्वितानक
- **अनुच्छेद 138:** उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता कीवृद्धि
- **अनुच्छेद 139:** कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना
- **अनुच्छेद 139-क:** कुछ मामलों का अंतरण
- **अनुच्छेद 140:** उच्चतम न्यायालय की आनुपर्याक शक्तियाँ
- **अनुच्छेद 141:** उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आवद्धकर होना
- **अनुच्छेद 142:** उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश
- **अनुच्छेद 143:** उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति
- **अनुच्छेद 144:** सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना
- **अनुच्छेद 145:** न्यायालय के नियम आदि
- **अनुच्छेद 146:** उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यव
- **अनुच्छेद 147:** निर्वचन

### भाग-6, अध्याय 5

#### उच्च न्यायालय ( 214-232 )

- **अनुच्छेद 214:** राज्यों के लिए उच्च न्यायालय
- **अनुच्छेद 215:** उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना
- **अनुच्छेद 216:** उच्च न्यायालयों का गठन
- **अनुच्छेद 217:** उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें
- **अनुच्छेद 218:** उच्चतम न्यायालय से संबोधित कुछ उपवंधों का उच्च न्यायालयों को लागू होना

## किंतु NCERT भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान सार संग्रह (By : Khan Sir, Patna)

- किस अनुच्छेद के अनुसार, उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, राष्ट्रपति के अनुमोदन से नियत करे? - **अनुच्छेद 130**
- किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को केंद्र एवं राज्यों के बीच या राज्यों में परस्पर न्यायाधीन विवादों का अवधारण करने की आरम्भिक और अनन्य अधिकारिता प्रदान की गयी है? - **अनुच्छेद 131**
- ऐसे विवाद जो केंद्रीय सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच हो या दो या अधिक राज्यों में हों, उच्चतम न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है? - **प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत**
- देश का उच्चतम अपीलीय न्यायालय कौन है? - **उच्चतम न्यायालय**
- सामान्यतः उच्चतम न्यायालय में अपील कब की जाती है?
  - जब कोई मामला संविधान की व्याख्या से संबंधित हो एवं विधि के प्रश्न से जुड़ा हो।
- अनुच्छेद 132 के तहत भारत के राज्यक्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की सिविल, दांडिक या अन्य कार्यवाही में दिये गये किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील किस न्यायालय में की जा सकेगी, यदि उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134क के अधीन यह प्रमाणित कर देता है कि उस मामले में संविधान के किसी पहलू का विश्लेषण करना आवश्यक हो? - **उच्चतम न्यायालय**
- किन मामलों में अपील स्वतः: उच्चतम न्यायालय के समक्ष पहुंच जाती है, यदि राज्य के उच्च न्यायालय ने नीचे की अदालत के किसी निर्णय को उलट कर अभियुक्त को मृत्युदंड दे दिया हो या उच्च न्यायालय किसी भी निम्न न्यायालय से अपने लिए कोई मामला उठा ले तथा अभियुक्त को मृत्युदंड दे दे? - **आपराधिक मामलों में**
- अनुच्छेद 136 के तहत उच्चतम न्यायालय किसी भी मामले में अपनी तरफ से विशेष अपील करने का अधिकार दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस विवेकाधीन शक्ति पर क्या कोई निर्वधन है? - **नहीं**
- अनुच्छेद 136 के अनुसार, किस न्यायालय को छोड़कर किसी भी उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध अपील की विशेष स्वीकृति देने पर उच्चतम न्यायालय पर कोई संवैधानिक प्रतिवधं नहीं है और यह बात स्वयं उच्चतम न्यायालय पर निर्भर करता है? - **संवैधानिक न्यायालय**
- संसद द्वारा बनायी गयी किसी विधि के या अनुच्छेद 145 के अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए अनुच्छेद 137 के तहत किस न्यायालय को अपने द्वारा सुनाये गये निर्णय या दिये गये किसी आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त है? - **उच्चतम न्यायालय**
- 42वें संविधान संशोधन, 1976 के द्वारा संविधान में कौन-सा एक नया अनुच्छेद जोड़कर उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार दिया गया कि वह शीघ्र न्याय दिलाने के उद्देश्य से किसी मुकदमे को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में भेज सकता है? - **अनुच्छेद 139ए**
- किसको यह अधिकार दिया गया है कि यदि वह उचित समझे कि किसी उच्च न्यायालय में सार्वजनिक हित से संबंधित कोई मामला लम्बित है और उसमें कोई महत्वपूर्ण कानूनी मुकदमा निहित है, तो वह उच्चतम न्यायालय से प्रार्थना कर सकता है कि उस मामलेको उच्च न्यायालय से मंगवा कर उच्चतम न्यायालय में निपटाया जाये? - **महान्यायवादी**
- किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित किया गया कानून भारत के क्षेत्र में स्थित सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होता है? - **अनुच्छेद 141**
- अनुच्छेद 143 के अनुसार, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से विधि से संबंधित या अन्य किसी विषय पर सलाह ले सकता है। क्या यह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है? - **नहीं**
- अनुच्छेद 219: उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान
- अनुच्छेद 220: स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि-व्यवसाय पर निर्वधन
- अनुच्छेद 221: न्यायाधीशों के वेतन आदि
- अनुच्छेद 222: किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को स्थानांतरण
- अनुच्छेद 223: कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति
- अनुच्छेद 224: अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति
- अनुच्छेद 224-क: उच्च न्यायालयों की वैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति
- अनुच्छेद 225: विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता
- अनुच्छेद 226: कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति
- अनुच्छेद 226-क: अनुच्छेद 226 के अंतर्गत कार्यवाइयों में केन्द्रीय अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं (निरसित)
- अनुच्छेद 227: सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति
- अनुच्छेद 228: कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण
- अनुच्छेद 228-क: राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के निस्तारण के लिए विशेष प्रावधान (निरसित)
- अनुच्छेद 229: उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय
- अनुच्छेद 230: उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्यक्षेत्र पर विस्तार
- अनुच्छेद 231: दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना
- अनुच्छेद 232: (निरसित)

## भारतीय न्यायपालिका

- राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्त्व के मामले एवं किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौता, प्रसंविदा आदि संबंधों पर उच्चतम न्यायालय से सलाह मांग सकता है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? - **अनुच्छेद 143**
- किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति को परामर्श देने से मना कर दिया था? - **अयोध्या से संवैधित बावरी मस्जिद के मामले में**  
उच्चतम न्यायालय को अपनी कार्यवाही तथा कार्यविधि को नियमित करने के लिए समय-समय पर नियमों के निर्माण करने की शक्ति किये अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है? - **अनुच्छेद 145 के अंतर्गत**
- राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से मांगी गयी सलाह पर कम से कम कितने न्यायाधीशों द्वारा सुनवाई की जानी चाहिए? - **कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा**
- उच्चतम न्यायालय को निम्न क्षेत्राधिकार, जैसे— मूल क्षेत्राधिकार, न्यायादेश क्षेत्राधिकार, अपीलीय, सलाहकार, अभिलेखों का न्यायालय, न्यायिक समीक्षा की शक्ति प्राप्त है, लेकिन कौन-सा क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय से कम है? - **मूल क्षेत्राधिकार**
- उच्चतम न्यायालय में कार्य करने वाले अधिवक्ताओं को वरिष्ठ अधिवक्ता, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एवं अन्य अधिवक्ता में विभाजित किया गया है, लेकिन केवल उच्चतम न्यायालय के समक्ष किसी रिकॉर्ड को कौन पेश कर सकता है? - **एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड**
- उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) संबंधी 99वें संशोधन विधेयक को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। परिणामस्वरूप न्यायाधीशों की नियुक्ति व स्थानांतरण के लिए कौन-सी पूर्ववर्ती प्रणाली ही लागू रहेगी? - **कॉलेजियम प्रणाली**
- 1993 में उच्चतम न्यायालय की नौ सदस्यीय संविधान पीठ ने निर्धारित किया कि मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति किस आधार पर ही होगी? - **वरिष्ठता क्रम के आधार पर**
- क्या उच्चतम न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश अवकाश प्राप्ति के पश्चात भारत की सीमा के अन्दर किसी भी न्यायालय में वकालत कर सकता है? - **नहीं**
- 44वें संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी संदेहों और विवादों की जांच कौन-सा न्यायालय करेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा? - **उच्चतम न्यायालय**
- उच्चतम न्यायालय अपना कार्य करने के लिए अपने पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। ये नियुक्तियां वह स्वयं और किस आयोग की सहायता से करता है? - **संघ लोक सेवा आयोग**
- संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों तथा अध्यक्ष को पदच्युत करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, किंतु वह किसकी जांच-पड़ताल करके उसको दोषी घोषित कर देने के बाद ऐसा करता है? - **उच्चतम न्यायालय**
- जनहित याचिकाओं का उद्देश्य लोगों के कल्याण में उन्नति करना और न्याय प्रदान करना होता है। इस तरह की याचिका दायर करने का अधिकार किन दो न्यायालयों को ही प्राप्त है? - **केवल उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय**
- जनहित याचिकाएं संविधान की न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति द्वारा संशोधित हुई हैं। इन याचिकाओं की धारणा मूलतः किस देश से ली गयी है? - **संयुक्त राज्य अमेरिका**
- भारत के किस पूर्व न्यायाधीश को भारत में जनहित याचिका (PIL: Public Interest Litigation) का जनक माना जाता है? - **न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती**
- क्या एक पोस्टकार्ड के माध्यम से लिखित रूप में जनहित याचिका दायर की जा सकती है? - **हाँ**
- 1979-80 के बाद से न्यायपालिका ने अपने पास आने वाले जनहित से जुड़े पत्रों (पोस्टकार्ड) को भी जनहित याचिका मानना शुरू कर दिया, फलतः यह किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? - **25 पैसे में न्याय**

## अध्याय 6

### अधीनस्थ न्यायालय (अनु 233-237)

- **अनुच्छेद 233:** जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति
- **अनुच्छेद 233क:** कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों का और उनके द्वारा किये गये निर्णयों आदि का विधिमान्यकरण
- **अनुच्छेद 234:** न्यायिक संवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती
- **अनुच्छेद 235:** अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण
- **अनुच्छेद 236:** निर्वचन
- **अनुच्छेद 237:** कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होता।

## भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं उनका कार्यकाल

1. **न्यायमूर्ति एच. जे. कानिया**  
26 जनवरी, 1950 से 6 नवंवर 1951
2. **न्यायमूर्ति एम. पतंजलि शास्त्री**  
7 नवंवर, 1951 से 3 जनवरी, 1954
3. **न्यायमूर्ति मेहर चंद महाजन**  
4 जनवरी, 1954 से 22 दिसंबर, 1954
4. **न्यायमूर्ति वी.के. मुखर्जी**  
23 दिसंबर, 1954 से 31 जनवरी, 1956
5. **न्यायमूर्ति एम.आर. दाम**  
1 फरवरी, 1956 से 30 सितंबर, 1959
6. **न्यायमूर्ति भुवनेश्वर प्रसाद मिहा**  
1 अक्टूबर, 1959 से 31 जनवरी, 1964
7. **न्यायमूर्ति पी.बी. गंगेन्द्र गडकर**  
1 फरवरी, 1964 से 15 मार्च, 1966
8. **न्यायमूर्ति ए.के. मरकारा**  
16 मार्च, 1966 से 29 जून, 1966
9. **न्यायमूर्ति के. मुख्याग्रव**  
30 जून, 1966 से 11 अप्रैल, 1967
10. **न्यायमूर्ति के.एन. बांचू**  
12 अप्रैल, 1967 से 24 फरवरी, 1968
11. **न्यायमूर्ति एम. हिंदायतुल्ला**  
25 फरवरी, 1968 से 16 दिसंबर, 1970
12. **न्यायमूर्ति जे.सी. शाह**  
17 दिसंबर, 1970 से 21 जनवरी, 1971

## किंदण NCERT भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान सार संग्रह (By : Khan Sir, Patna)

- भारत में सबसे पहले 1979 में किस न्यायमूर्ति ने जनहित याचिका के रूप में 'हुसैनगारा खातून बनाम बिहार सरकार' के एक ऐसे मामले की सुनवाई करने का निर्णय लिया, जिसे पोडित व्यक्तियों ने नहीं, बल्कि उनकी ओर से दूसरों ने दाखिल किया था?

न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती

- किसको 'न्यायिक गतिशीलता' के रूप में जाना जाता है और जो 'न्यायिक संयम' (Judicial Restraint) का प्रतिवाद है? - **न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism)**
- कौन-सी याचिका न्यायिक सक्रियता का सबसे प्रभावी माध्यम बन गयी है? - **जनहित याचिका**
- न्यायिक सक्रियता की अवधारणा किस देश के संघीय अदालतों से निकली अवधारणा है, जिसमें संविधान की व्याख्या का अधिकार न्यायपालिका के दायरे में रखकर एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व बनाया गया? - **अमेरिका**
- न्यायिक सक्रियता (Judicial Activism) शब्द का सबसे पहले 1947 में किस अमेरिकी ने किया था? - **आर्थर लेस्लिंगर जूनियर**

### उच्च न्यायालय

- किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा? - **अनुच्छेद 214 में**
- संसद द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों के लिए या दो या दो से अधिक राज्यों तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? - **अनुच्छेद 231**
- किस संविधान संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक साझा उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है? - **सातवें संशोधन अधिनियम, 1956**
- वर्तमान भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। देश में कितने ऐसे उच्च न्यायालय हैं, जो दो या अधिक राज्यों अथवा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए स्थापित किये गये हैं? - **8 उच्च न्यायालय**
- एक उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र के विस्तार की शक्ति किसके पास होती है? - **संसद के पास**
- किस अनुच्छेद में कहा गया है कि उच्च न्यायालय भी उच्चतम न्यायालय की तरह एक अभिलेख न्यायालय है? - **अनुच्छेद 215 में**
- उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करने का अधिकार संसद को है, जबकि उच्च न्यायालयों की न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करने का अधिकार किसको प्राप्त है? - **राष्ट्रपति को**
- उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? - **राष्ट्रपति द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श के बाद**
- उच्च न्यायालय का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है? - **अनुच्छेद 216**
- किस अनुच्छेद के अनुसार, उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश एवं उतनी संख्या में अन्य न्यायाधीश होते हैं जितनी समय-समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है? - **अनुच्छेद 216 के अनुसार**
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी उसी प्रक्रिया से हटाया जाता है, जिस प्रकार अनुच्छेद 124(4) के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। इस प्रावधान का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? - **अनुच्छेद 217(1 खं)**
- भारत में अभी तक कितने उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को इस प्रकार हटाया गया है? - **एक भी नहीं**
- अनुच्छेद 217(1) के तहत उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश अपने पद पर 62 वर्ष की आयु तक रह सकता है। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? - **कार्यकाल निर्धारित नहीं है**

- 13. न्यायमूर्ति एस.एम. मिकारी 22 जनवरी, 1971 से 25 अप्रैल, 1973
- 14. न्यायमूर्ति अर्जीत नाथ 26 अप्रैल, 1973 से 28 जनवरी, 1977
- 15. न्यायमूर्ति एम.एच. थंग 29 जनवरी, 1977 से 21 फरवरी, 1978
- 16. न्यायमूर्ति यशवंत विण् चंद्रचूड़ 22 फरवरी, 1978 से 11 जुलाई, 1985
- 17. न्यायमूर्ति पी.एन. भगवती 12 जुलाई, 1985 से 20 दिसंबर, 1986
- 18. न्यायमूर्ति रघुनंदन स्वरूप पाठक 21 दिसंबर, 1986 से 18 जून, 1989
- 19. न्यायमूर्ति डॉ.एम. वंकटगापन 19 जून, 1989 से 17 दिसंबर, 1989
- 20. न्यायमूर्ति सव्यमाची मुखर्जी 18 दिसंबर, 1989 से 25 सितंबर, 1990
- 21. न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा 26 सितंबर, 1990 से 24 नवंबर, 1991
- 22. न्यायमूर्ति के.एन. मिंह 25 नवंबर, 1991 से 12 दिसंबर, 1991
- 23. न्यायमूर्ति एम.एच. कानिया 13 दिसंबर, 1991 से 17 नवंबर, 1992
- 24. न्यायमूर्ति ललित मोहन शर्मा 18 नवंबर, 1992 से 11 फरवरी, 1993
- 25. न्यायमूर्ति एम.एन. वंकटचलेया 12 फरवरी, 1993 से 24 अक्टूबर, 1994
- 26. न्यायमूर्ति ए.एम. अहमदी 25 अक्टूबर, 1994 से 24 मार्च, 1997
- 27. न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा 25 मार्च, 1997 से 17 जनवरी, 1998
- 28. न्यायमूर्ति एम.एम. पुंछी 18 जनवरी, 1998 से 9 अक्टूबर, 1998
- 29. न्यायमूर्ति डॉ. ए.एस. आनंद 10 अक्टूबर, 1998 से 31 अक्टूबर, 2001
- 30. न्यायमूर्ति एस.पी. भरुचा 1 नवंबर, 2001 से 5 मई, 2002
- 31. न्यायमूर्ति बी.एन. किरपाल 6 मई, 2002 से 7 नवंबर, 2002
- 32. न्यायमूर्ति जी.बी. पटनायक 8 नवंबर, 2002 से 18 दिसंबर, 2002
- 33. न्यायमूर्ति बी.एन. छोरे 19 दिसंबर, 2002 से 1 मई, 2004
- 34. न्यायमूर्ति एस. राजेंद्र वावृ 2 मई, 2004 से 31 मई, 2004

भारतीय न्यायपालिका

उच्च न्यायालय-अधिकारिता और अवस्थान

## उच्च न्यायालय-अधिकारिता और अवस्थान

| उच्च न्यायालय    | स्था. वर्ष | अधिकारिता                             | अवस्थान  |
|------------------|------------|---------------------------------------|--|
| इलाहाबाद         | 1866       | उत्तर प्रदेश                          | इलाहाबाद (लखनऊ में खंडपीठ)                               |
| आंध्र प्रदेश     | 1954       | आंध्र प्रदेश, तेलंगाना                | हैदराबाद   |
| बम्बई            | 1862       | महाराष्ट्र, दादरा एवं नगर हवेली, गोवा | मुम्बई (नागपुर, पणजी और औरंगाबाद, दमन और दीव में खंडपीठ) |
| कलकत्ता          | 1862       | पश्चिम बंगाल, अंडमान व निकोबार        | कोलकाता (पोर्ट ब्लेयर में खंडपीठ)                        |
| दिल्ली           | 1966       | दिल्ली                                | दिल्ली   |
| गुवाहाटी         | 1948       | असम, मणिपुर, मेघालय, नगालैंड          | गुवाहाटी (कोहिमा में खंडपीठ और शिलांग में सर्किट खंडपीठ) |
| गुजरात           | 1960       | गुजरात                                | अहमदाबाद   |
| हिमाचल प्रदेश    | 1971       | हिमाचल प्रदेश                         | शिमला  |
| जम्मू-कश्मीर     | 1928       | जम्मू-कश्मीर, लद्दाख                  | श्रीनगर और जम्मू   |
| कर्नाटक          | 1884       | कर्नाटक                               | बंगलौर   |
| केरल             | 1958       | केरल, लक्ष्मीप                        | एर्नाकुलम  |
| मध्य प्रदेश      | 1956       | मध्य प्रदेश                           | जबलपुर (ग्वालियर और इंदौर में खंडपीठ)                    |
| मद्रास           | 1862       | तमिलनाडु, पांडिचेरी                   | मद्रास   |
| ओडिशा            | 1948       | ओडिशा                                 | कटक  |
| पटना             | 1916       | बिहार                                 | पटना   |
| पंजाब और हरियाणा |            | पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़               | चंडीगढ़  |
| राजस्थान         | 1949       | राजस्थान                              | जोधपुर (जयपुर में खंडपीठ)                                |
| सिक्किम          | 1975       | सिक्किम                               | गंगटोक   |
| छत्तीसगढ़        | 2000       | छत्तीसगढ़                             | बिलासपुर   |
| झारखंड           | 2000       | झारखंड                                | रांची  |
| उत्तराखण्ड       | 2000       | उत्तराखण्ड                            | नैनीताल  |
| मणिपुर           | 2013       | मणिपुर                                | इम्फाल   |
| मेघालय           | 2013       | मेघालय                                | शिलांग   |
| त्रिपुरा         | 2013       | त्रिपुरा                              | अगरतला   |
| तेलंगाना         | 2019       | तेलंगाना                              | हैदराबाद   |

- उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए उसे भारत का नागरिक होना, भारत में कम से कम 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर रहना, तथा किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय या एक से अधिक राज्यों के उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहना आवश्यक है। यह प्रावधान किस अनच्छेद में किया गया है?

- अनुच्छेद 217( 2 )

35. न्यायमूर्ति रमेश चंद्र लाहोटी  
1 जून, 2004 से 31 अक्टूबर, 2005

36. न्यायमूर्ति वाई.के. सभरवाल  
1 नवंबर, 2005 से 13 जनवरी, 2007

37. न्यायमूर्ति के.जी. बालाकृष्णन  
14 जनवरी, 2007 से 11 मई, 2010

38. न्यायमूर्ति एस.एच. कपाड़िया  
12 मई, 2010 से 28 सितंबर, 2012

39. न्यायमूर्ति अल्टमस कबीर  
29 सितंबर, 2012 से 18 जुलाई, 2013

40. न्यायमूर्ति पी. सदाशिवम  
19 जुलाई, 2013 से 26 अप्रैल, 2014

41. न्यायमूर्ति आर.एम. लोढा  
27 अप्रैल, 2014 से 27 सितंबर, 2014

42. न्यायमूर्ति एच.एल. दत्तू  
28 सितंबर, 2014 से 02 दिसंबर, 2015

43. न्यायमूर्ति टी.एस. ठाकुर  
03 दिसंबर, 2015 से 03 जनवरी, 2017

44. न्यायमूर्ति जगदीश खेहर  
04 जनवरी, 2017 से 27 अगस्त, 2017

45. न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा  
28 अगस्त, 2017 से 02 अक्टूबर, 2018

46. न्यायमूर्ति रंजन गोगोई  
03 अक्टूबर, 2018 से 17 नवंबर, 2019

47. न्यायमूर्ति शरद अरविंद बोबडे  
18 नवंबर, 2019 से 23 अप्रैल, 2021

लोक अदालत

लोक अदालत एक ऐसा मंच है, जहां न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों में या मुकदमेबाजी से पहले के स्तर के विवादों को प्री-लिटिगेशन स्तर पर आपसी समझौता वार्ता से निपटाया जाता है। लोक अदालतों को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 19 के तहत कानूनी दर्जा दिया गया है। पूरे देश में ताल्लुका, जिला, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय स्तर पर इन अदालतों का गठन किया गया है। लोक अदालतों द्वारा दिये गये फैसले को दीवानी अदालत की डिक्री माना जाता है, जो अंतिम और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है। उसके खिलाफ कोई अपील नहीं की जा सकती। साथ ही, इन अदालतों

## किंतु NCERT भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान सार संग्रह (By : Khan Sir, Patna)

- अनुच्छेद 219 के अनुसार, उच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश अपना पद ग्रहण करने से पहले किसके समक्ष शपथ ग्रहण करता है? - **राज्यपाल के समक्ष**
- यदि कोई उच्च न्यायालय दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही है तो उस न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन शपथ दिलाता है?
  - वह राज्यपाल जिसके गन्य के क्षेत्र में उच्च न्यायालय स्थित है
- यदि उच्च न्यायालय किसी संघ राज्य क्षेत्र में स्थित है तो उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन शपथ दिलाता है?
- किस अनुच्छेद के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय तथा अन्य उच्च न्यायालयों को छोड़कर बकालत करने पर प्रतिबंध लगाता है? - **अनुच्छेद 220**
- अनुच्छेद 223 के तहत उच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, किंतु अनुच्छेद 224 के तहत उच्च न्यायालय के कार्यों में बढ़ोत्तरी हो जाने पर किन न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है?
  - अपर तथा अन्य कार्यकारी न्यायाधीशों की कितने वर्षों के लिए की जा सकती है? - **2 वर्ष के लिए**
- उच्च न्यायालयों में अपर तथा अन्य कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति अधिकतम करता है? - **उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु संबंधी विवादों का निर्धारण संसद द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या विहित प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है, परंतु उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में विवाद का निर्णय कौन करता है?**
  - **राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की सलाह से किस अनुच्छेद के अनुसार, उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए ही नहीं, अपितु अन्य प्रयोजनों या उद्देश्यों के लिए भी रिट जारी कर सकता है?**
- किस अनुच्छेद के अनुसार, उच्च न्यायालय को अपने अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण का अधिकार देता है, अपने अधीनस्थ किसी भी न्यायालय के निर्णय की पूछताछ कर सकता है, तथा अधीनस्थ न्यायालय की कार्य प्रणाली, रिकॉर्ड, रजिस्टर तथा हिसाब आदि के बारे में नियम आदि बना सकता है? - **अनुच्छेद 226**
- अनुच्छेद 227 के तहत किये गये वर्तमान प्रावधानों को किस संशोधन द्वारा प्रस्थापित किया गया?
  - **44वें संविधान संशोधन द्वारा**
- सिविल तथा आपराधिक दोनों प्रकार के मामलों में अपील के लिए सर्वोच्च न्यायालय किसे कहता है?
  - **उच्च न्यायालयों को**
- पेटेंट तथा डिजाइन, उत्तराधिकार, भूमि प्राप्ति, दिवालियापन और संरक्षण इत्यादि अभियोगों में किस न्यायालय में अपील की जा सकती है?
  - **उच्च न्यायालय**
- भारत में उच्च न्यायालय संस्था के रूप में कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास उच्च न्यायालयों का गठन कब किया गया था?
  - **1862 में**
- कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास के अलावा और कितने उच्च न्यायालय हैं, जिनका गठन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किया गया? - **तीन (इलाहाबाद, पटना और जम्मू-कश्मीर)**
- भारत क्षेत्र में स्थित किन उच्च न्यायालयों को अन्य उच्च न्यायालयों से अधिक शक्तियां प्राप्त हैं?
  - **चेन्नई, कोलकाता एवं मुम्बई उच्च न्यायालयों को**
- किन विषयों पर उच्च न्यायालयों को प्रारम्भिक अधिकारिता प्राप्त है?
  - **मूल अधिकार, वसीयत, विवाह, विवाह विच्छेद, कंपनी मामलों में कौन-से प्रश्न उच्च न्यायालय में निर्णीत नहीं किये जा सकते हैं?**
- **संविधान की व्याख्या संबंधी**

के माध्यम से निर्णीत प्रकरणों की कोर्ट फीस भी पूर्णतः वापस हो जाती है। लोक अदालतों में रखे जाने वाले मामले इस प्रकार हैं— वैवाहिक एवं पारिवारिक मामले, भूमि अधिग्रहण संबंधी मामले, श्रम एवं औद्योगिक विवाद, कामगारों के मामले, पेंशन संबंधी मामले, आवास बोर्ड और मलिन बस्ती निपटान मामले तथा गृहत्रयण मामले, उपभोक्ता शिकायत मामले, विजली संबंधित मामले, टेलीफोन बिल के मामले, गृह कर सहित नगरपालिका संबंधी मामले, सेल्यूलर कम्पनियों के मामले, बैंक बसूली मामले, मोटर वाहन दुर्घटना संबंधी प्रकरण आदि।

### परिवार न्यायालय

परिवार न्यायालयों की स्थापना परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 द्वारा की गयी है, जिसका मुख्य उद्देश्य विवाह तथा अन्य पारिवारिक मुद्दों को निपटाना है। राज्य सरकार उन क्षेत्रों में जहां की आबादी 10 लाख से अधिक हो, अथवा जहां आवश्यक समझे, परिवार न्यायालय की स्थापना कर सकती है। कुल मिलाकर इन न्यायालयों की स्थापना का अर्थ है— पारिवारिक वातावरण में सौहार्दपूर्ण स्थिति उत्पन्न करना। साथ ही, यदि कोई पारिवारिक समस्या है तो उसका वथाशीष्ट समाधान करना। गैरतलब है कि इन निर्णयों में कुटुम्ब संघों की मदद ली जा सकती है। परिवार न्यायालय के आदेशों एवं निर्णयों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

### ग्राम न्यायालय

ग्रां-ग्रां तक त्वरित एवं सस्ता न्याय पहुंचाने के उद्देश्य हेतु संसद ने दिसंबर 2008 में ग्राम न्यायालय विधेयक पारित हुआ तथा यह अधिनियम के रूप में 2 अक्टूबर, 2009 से प्रभावी हुआ। यह अधिनियम जम्मू-कश्मीर, नगालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एवं जनजाति क्षेत्रों को छोड़कर समस्त भारत पर प्रभावी

## भारतीय न्यायपालिका

उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति राज्य विधानमंडल व केंद्र सरकार द्वारा के अधिनियमों एवं कार्यकारी आदेशों को संवैधानिकता के परीक्षण के लिए है। यह ज्ञावधान किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया?

- 43वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1977

### अधीनस्थ न्यायालय

उच्च न्यायालय के नीचे के सोपानक्रम पर स्थित सभी न्यायालयों को क्या कहा जाता है?

- अधीनस्थ न्यायालय

न्यायिक क्षेत्र के सबसे निम्न स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 233 के अंतर्गत किसके द्वारा की जाती है?

- राज्यपाल द्वारा

जिला न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है?

- उच्च न्यायालय द्वारा

उच्च न्यायालय की सिफारिश पर राज्यपाल उस व्यक्ति को जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर सकता है जो, कम से कम कितने वर्ष तक किसी न्यायालय में अधिकार रहा हो?

- 7 वर्ष तक

जिला न्यायाधीश जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। उसे सिविल एवं आपाधिक मामलों में मूल एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त होते हैं। जब जिला न्यायाधीश जौबदारी मामलों को सुनवाइं करता है, तो उसे क्या कहा जाता है? - सत्र न्यायाधीश

अधीनस्थ न्यायालयों को अधिकारिताएं, शक्तियां और कार्य मुख्यतः सिविल प्रक्रिया संहिता, 1973 से तब होते हैं। संसद द्वारा पारित कुछ अधिनियमों के द्वारा भी इन न्यायालयों को कुछ अधिकारिताएं दी गयी हैं। इसके दो प्रमुख उदाहरण कौन-से हैं?

- औद्योगिक विवाद अधिनियम तथा हिंदू विवाह अधिनियम

किस अधिनियम के अधीन भारत में कुटुम्ब या पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना की गयी है तथा इस अधिनियम के द्वारा न्यायालय को पारिवारिक विवादों में मैत्रीपूर्ण सन्झौतों को बढ़ावा देने के लिए स्वविवेक का प्रयोग करने का अधिकार दिया गया है?

- कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984

कुटुम्ब न्यायालयों के नियंत्रण एवं आदेशों के विरुद्ध अपील कहां की जा सकती है?

- उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में

लोक अदालत ऐसा मंच है, जहां अदालत में मामला दायर किये बिना विवादों का सद्भावनामूर्ग ढंग से निवारा किया जाता है। इन अदालतों को किस अधिनियम के द्वारा कानूनी दर्जा दिया गया है? - विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987

लोक अदालतों की व्यवस्था विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत की गयी है। लोक अदालत किस प्रकार के बाद का निपटारा करती है?

- सिविल प्रकृति के लगभग सभी विवाद, जैसे- विवाह संबंधी, भूमि संबंधी,

सम्पत्ति के बंटवारे संबंधी विवाद तथा श्रम विवाद

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 में वर्ष 2002 में संशोधन करके किस प्रकार की अदालतों का प्रावधान किया गया है? - स्थायी लोक अदालतों का

लोक अदालत के नियंत्रण के खिलाफ किसी अपील का प्रावधान नहीं है, क्योंकि इसमें नियंत्रण दोनों पक्षों की सहमति से होता है। अनुच्छेद 226 के तहत किस न्यायालय में इसके खिलाफ अपील नहीं कर सकते?

- उच्च न्यायालय

परन्तु मैं इलैल, सौंदेवाजी या प्लॉवर्डेनिंग को व्यवस्था केवल उन मामलों में लागू है, जिनमें अधिकतम कितने वर्ष के कारावास का प्रावधान है? - सात वर्ष

किस न्यायालय की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य 'न्याय आपके द्वार' सिद्धांत को प्रायोगिकरूप में लाना है, ताकि न्याय ग्रामीणों के पास ही उपलब्ध हो सके? - ग्रामीण न्यायालय

है। इसके तहत खण्डस्तर पर 5,067 ग्राम न्यायालय स्थापित किये जाने की योजना थी। इस अधिनियम के मुताबिक राज्य सरकार संबद्ध उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद अधिसूचना के द्वारा पंचायत समिति स्तर पर एक या अधिक ग्राम न्यायालय का गठन कर सकेगी। राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के परामर्श से, प्रत्येक ग्राम न्यायालय के लिए एक न्यायाधिकारी नियुक्त करेगी एवं ऐसा न्यायाधिकारी प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य होना चाहिए। ग्राम न्यायालय को ऐसे आपराधिक, दीवानी मामले, दावों एवं विवादों को स्वीकार करने का अधिकार है जिनमें मृत्युदंड, आजीवन कारावास एवं दो वर्ष से अधिक की सजा का प्रावधान न हो। चोरी एवं संपत्ति संबंधी मामले ग्राम न्यायालय में स्वीकार किये जा सकते हैं। ग्राम न्यायालय को दीवानी न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं। इन न्यायालयों की स्थापना एवं संचालन संबंधी व्यवहार को संबंधित सरकार वहन करती है।

### भारत में जनहित याचिका

जनहित याचिका (PIL: Public Interest Litigation) एक ऐसा माध्यम है, जिसमें मुकदमेबाजी या कानूनी कार्यवाही के द्वारा अल्पसंख्यक या वर्चित समूह या व्यक्तियों से जुड़े सार्वजनिक व जनहित के मुद्दों को उठाया जाता है। वस्तुतः जनहित याचिका न्यायिक सक्रियता का नतीजा है, जिसके माध्यम से एक व्यक्ति या एक गैर-सरकारी संगठन या नागरिक समूह, अदालत में ऐसे मुद्दों पर न्याय की मांग कर सकता है जिसमें एक बड़ा सार्वजनिक हित जुड़ा होता है। इसका उद्देश्य सामान्य लोगों को अधिक से अधिक कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए न्यायपालिका तक पहुंच प्रदान करना है। कोई भी भारतीय नागरिक जनहित याचिका दायर कर सकता है, केवल शर्त यह है कि इसे निजी हित के बजाय सार्वजनिक हित में दायर किया जाना चाहिए। यदि कोई मुद्दा अत्यंत सार्वजनिक महत्व का है

### विविध

- कौन-सा न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय होता है? - **मंत्र न्यायालय**
- वह न्यायालय कौन-सा है जिसको लोकसभा या विधानसभा के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर निर्णय लेने की मूल अधिकारिता प्राप्त है? - **उच्च न्यायालय**
- एक उच्च न्यायालय से दूसरे किसी न्यायाधीश के स्थानांतरण के लिए कौन प्राधिकृत है? - **राष्ट्रपति**
- उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का वह रिट/आदेश कौन-सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है? - **अधिकारपृच्छा रिट**
- उच्चतम न्यायालय के 'न्यायिक पुनरीक्षण' कार्य का क्या अर्थ है? - **कानूनों की सांविधानिक वैधता का परीक्षण**
- उच्चतम न्यायालय ने हमारे संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा किस मामले में की थी? - **केशवानंद भारती का मामला**
- उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है यदि सत्र न्यायालय ने दंड दिया हो? - **मात्र वर्ष या अधिक का**
- उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में मौलिक अधिकारों की प्रमुखता राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों के ऊपर स्थापित की? - **गोलकनाथ का मामला**
- भारतीय संविधान की व्याख्या के लिए अंतिम प्राधिकारी कौन है? - **उच्चतम न्यायालय**
- संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? - **उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों**
- किसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा लोकसभा अध्यक्ष के पदों को सुशोभित किया? - **के.एस. हेगडे**
- सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? - **जस्टिस एम. फातिमा बीबी**
- न्यायपालिका द्वारा बनाये गये कानून को क्या कहते हैं? - **निर्णय विधि**
- अंतर्राज्यीय विवाद संबंधी मामलों पर विचार करने के लिए कौन एक संघीय न्यायालय के रूप में काम करता है? - **उच्चतम न्यायालय**
- भारत के वह मुख्य न्यायमूर्ति कौन है, जिन्हें भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ था? - **न्यायमूर्ति एम. हिदायतुल्ला**
- राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? - **राज्यपाल**
- जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है? - **उच्च न्यायालय**
- किस उच्च न्यायालय को पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के होने का गौरव प्राप्त है? - **हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय**
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही अक्षमता है? - **विशेष बहुमंख्या सहित संसद के दोनों सदन**
- भारत में वर्ष 2009 में किस उच्च न्यायालय ने समलैंगिक यौन संबंधों को कानूनी करार दिया? - **दिल्ली**
- नियेथ का आदेश उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय द्वारा किसके द्वारा जारी होता है? - **न्यायिक या अर्ध-न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध**
- भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। इसका क्या आशय होता है? - **इसके सभी निर्णयों का साक्षात्कार मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्नचिह्न नहीं लगाया जा सकता है**
- भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? - **अनुच्छेद 134ए को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना**

तो कई बार न्यायालय भी ऐसे मामले में स्वतः संज्ञान लेती है और ऐसे मामले को संभालने के लिए एक वकील को नियुक्त करती है। जनहित याचिकाओं को कंबल उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में दायर किया जा सकता है। जनहित याचिका दायर करने वाला व्यक्ति खुद भी वहस कर सकता है या एक वकील को नियुक्त कर सकता है। भारत के **न्यायमूर्ति एवं एन. भगवती** को भारत में पीआईएल का जनक माना जाता है।

### अन्य प्रमुख बिंदु

- 1999 में शेंटी आयोग ने न्यायिक अधिकारियों के बेतन-भत्तों में वृद्धि करने एवं अधीनस्थ न्यायालयों के लिए एक रूप सेवा शर्तें लागू करने का सुझाव दिया।
- मलिमथ समिति ने वर्ष 2003 में न्यायाधीशों की अहंता को समीक्षा करने का प्रस्ताव रखा ताकि उच्च क्षमता वाले न्यायाधीशों की नियुक्ति हो सके और सभी न्यायाधीशों को न्यायालय प्रवंध में प्रशिक्षण प्रदान किया जाये।
- 11वें वित्त आयोग ने 1784 फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का सुझाव दिया था। ये मामले अधिकतर सेशन कोर्ट में लम्बित पड़े हैं।
- ओडिशा, उत्तर प्रदेश एवं तमिलनाडु में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने लम्बित मामलों के निपटारे में सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है।
- बिहार में फास्ट ट्रैक कोर्ट की संख्या सर्वाधिक है, लेकिन बिहार में लम्बित मामलों की संख्या के लिहाज से यह अन्य राज्यों के मुकाबले दूसरे स्थान पर है।
- त्वरित न्याय प्रदान करने और विधि सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन की स्थापना जून 2011 में की गयी ताकि न्याय प्रदान करने में देरी एवं लम्बित मामलों को कम करके न्याय प्रणाली तक पहुंच बढ़ाया जा सके।